शनिवार, 16 मई 2026

मौसम

तापमान 28 – 36
आर्द्रता 72%
सूर्योदय: 04:56 सूर्यास्त: 18:09

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

Epaper.samagya.in

समाज्ञा

हावड़ा : सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट जागरूकता अभियान

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

कोलकाता, ज्येष्ठ कृष्णपक्ष अमावस्या, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

सुविचार : वक्त वो जज है जो बिना अदालत के फैसला सुना देता है।

RED-X
B.W.P. PLY,
BOARDS& DOORS
'X' Factor that Makes A Difference
Stockist :
GULAB CHAND
LAL CHAND& Co.
9831114555
9874415555

आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामला में बड़ी कार्रवाई, पूर्व कमिश्नर समेत तीन आईपीएस अधिकारी निलंबित

तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू, कॉल रिकॉर्ड की भी होगी जांच

पूर्व मुख्यमंत्री ममता की भूमिका की भी होगी जांच, शुभेंदु ने की घोषणा

कोलकाता, समाज्ञा : आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या मामले की फाइल फिर से खोले जाने संबंधी भाजपा के चुनाव पूर्व किए गए वादे पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान कथित लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के मद्देनजर निलंबित करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों अधिकारियों ने मामले में कथित तौर पर लापरवाही बरती थी, 'पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत के रूप में पैसे की पेशकश' की और अगस्त 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के संबंध में एक 'अनधिकृत संवाददाता सम्मेलन' को संबोधित किया। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराध की वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच राज्य की गृह सचिव संघमित्रा घोष के नेतृत्व में मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के मार्गदर्शन में की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई मेरे आदेश पर मुख्य सचिव और गृह सचिव द्वारा किए गए प्रारंभिक तथ्य-जांच पर आधारित है। हमने जांच को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए तीनों अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हम केवल कोलकाता पुलिस की भूमिका और मामले को कथित तौर पर गलत तरीके से संभालने के मामले की जांच कर रहे हैं। हम यह जांच करेंगे कि पुलिस जैसे अनुशासित बल ने प्राथमिकी दर्ज करने आदि में उचित भूमिका निभाई या नहीं। हम संदिग्धों के फोन कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट में पिछली सरकार की संभावित भूमिका की जांच करेंगे। संदिग्धों से पूछताछ के अलावा, जरूरत पड़ने पर हम पीड़ित के माता-पिता से भी बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाला अधिकारी न तो शहर पुलिस के प्रवक्ता थे और न ही राज्य गृह विभाग के। अधिकारी ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और उसे संबोधित किया। उस संवाददाता सम्मेलन में उनके भाषण का लहजा और शैली महिलाओं और उनके सशक्तीकरण के विचार के प्रति अनादरपूर्ण थी। क्या उन्होंने सरकार के मौखिक निर्देशों के तहत काम किया, यह जांच का हिस्सा होगा। कथित रिश्वतखोरी के प्रयास का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया कि दो वरिष्ठ अधिकारी उनके घर आए थे और सरकार की ओर से उन्हें पैसे की पेशकश की थी। इस आरोप की जांच होनी चाहिए।

प्रेसिडेंसी जेल में से 23 मोबाइल बरामद, सुपरिटेंडेंट समेत दो अधिकारी निलंबित, सीआईडी जांच के आदेश

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को जेल के अंदर कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों में प्रेसिडेंसी सुधार गृह के अधीक्षक और मुख्य नियंत्रक को निलंबित कर दिया। राज्य सचिवालय नवान्न में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रेसिडेंसी सुधार गृह के अंदर स्मार्टफोन सहित मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जेल अधिकारियों का एक वर्ग इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की ओर से समर्थन या उदासीनता भी हो सकती है। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई और महानिदेशक (सुधार सेवा) के माध्यम से इसका सत्यापन किया गया। अधिकारी ने बताया कि जेल अधिकारियों और कोलकाता पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान जेल परिसर से 23 मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि प्रेसिडेंसी जेल के अधीक्षक एन. कुजूर और मुख्य नियंत्रक दीप्ता घराई को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कई सुधारगृहों में बंद कैदी जेल की दीवारों के भीतर से ही संगठित अपराध नेटवर्क चला रहे थे। अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में फैला पूरा आपराधिक नेटवर्क जेलों से संचालित हो रहा है। यह कोई नयी बात नहीं है। यह वर्षों से चल रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। इसे खत्म करने में समय लगेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि दमदम केंद्रीय जेल से लेकर बरहामपुर तक कई सुधारगृहों से इसी तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में, जैसे कि शेख शाहजहां (संदेशखलि मामले के आरोपी) के मामले में, जेल से ही नेटवर्क चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्तव्य में लापरवाही होने पर न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जेल परिसर में सिम कार्ड और मोबाइल फोन कैसे पहुंचे, मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए सीआईडीको भी आदेश दिया।

मुख्यमंत्री शुभेंदु सप्ताह में दो बार 'जनता दरबार' आयोजित करेंगे, सुनेंगे लोगों की फरियाद

कोलकाता, समाज्ञा : बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब शासन शैली में भी बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे आम जनता से जुड़ने के लिए 'जनता दरबार' शुरू करने का निर्णय लिया है। नवान्न (राज्य सचिवालय) सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सप्ताह में एक या दो दिन, निर्धारित दो घंटों के लिए आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे। हालांकि, राज्य प्रशासन की ओर से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन सचिवालय में इसकी तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गई हैं। सूत्रों का दावा है कि इस 'जनता दरबार' के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शासन के एक या दो शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि समस्याओं का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। संभवतः एक जून से इस पहल की शुरुआत हो सकती है।

विदेश यात्रा पर कर लगाने की सरकारी योजना संबंधी खबर गलत : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को उन खबरों को पूरी तरह से फर्जी बताया जिनमें कहा गया था कि सरकार विदेश यात्रा पर कर, उपकर या अधिभार लगाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह बात एक खबर की प्रतिक्रिया में कही, जिसमें कहा गया है कि सरकार विदेशी यात्रा पर कर, उपकर या अधिभार लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, यह सरासर झूठ है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेशी यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए 'कारोबार सुगमता' और 'जीवन सुगमता' को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं मीडिया में आयी किसी खबर का खंडन किया हो।

रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ अबतक के सबसे निचले स्तर 95.81 प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई : अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 17 पैसे की गिरावट के साथ 95.81 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा है। कारोबार के दौरान एक समय यह 96 प्रति डॉलर के से नीचे चला गया था। रुपया इस वर्ष अब तक छह प्रतिशत से अधिक टूट चुका है और पिछले छह कारोबारी सत्रों में यह लगभग दो प्रतिशत कमजोर हुआ है। अमेरिका की मजबूत खुदरा बिक्री और स्थिर श्रम बाजार के आंकड़ों के बाद डॉलर सूचकांक मजबूत हुआ।

भोजशाला सरस्वती मंदिर घोषित

उच्च न्यायालय ने परिसर में नमाज अदा करने का आदेश रद्द किया

- हिंदू पक्ष ने कहा, '700 साल के संघर्ष में जीत हुई'
- शीर्ष अदालत जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष

इंदौर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के ऐतिहासिक विवाद के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इस मध्यकालीन स्मारक की धार्मिक प्रकृति हिंदू मान्यताओं में 'ज्ञान की देवी' के रूप में पूजी जाने वाली वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर के तौर पर तय की। अदालत ने रेखांकित किया कि परमार वंश के राजा भोज की विरासत से जुड़े इस स्थल पर हिंदुओं की पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है। उच्च न्यायालय ने विवादित परिसर में केवल हिंदुओं को उपासना का अधिकार दिए जाने की गुहार स्वीकार की और इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सात अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार स्मारक में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने इस मामले से संबंधित पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर पुरातात्विक व ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की अधिसूचनाओं व उसके वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कानूनी प्रावधानों की रोशनी में फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मुकदमे में शीर्ष अदालत के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। खंडपीठ ने सामाजिक संगठन 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' और कुलदीप तिवारी व अन्य लोगों की दायर दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं मंजूर करते कहा,''भोजशाला परिसर और कमाल मौला मस्जिद के विवादित क्षेत्र का धार्मिक स्वरूप वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर वाली भोजशाला के रूप में तय किया जाता है।'' खंडपीठ ने पाया कि इस स्थल पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है, भले ही समय के साथ इसे विनियमित किया गया हो। अदालत ने कहा, हम इस निष्कर्ष को दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य ने स्थापित किया है कि विवादित क्षेत्र का स्वरूप भोजशाला के रूप में था जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत अध्ययन केंद्र था और राजा भोज के काल से संबंधित संदर्भों सहित साहित्य और स्थापत्य-संबंधी संदर्भ संकेत देते हैं कि धार में देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर विद्यमान था।

भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की

नयी दिल्ली : हिंदू पक्ष के एक याचिकाकर्ता की तरफ से शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दाखिल की गई, जिसमें अनुरोध किया गया कि भोजशाला परिसर विवाद मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर कोई भी आदेश उसका पक्ष सुने बिना पारित नहीं किया जाए। जितेंद्र सिंह 'विशेन' द्वारा वकील बरुण कुमार सिन्हा के जरिए दायर की गई कैविएट अर्जी में कहा गया, ''नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिए बिना उपरोक्त मामले में कोई आदेश न दिया जाए।'' कैविएट अदालत को दी गई एक तरह की पूर्व सूचना या अनुरोध होता है।

पेट्रोल, डीजल की कीमत तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ी, सीएनजी दो रुपये प्रति किलोग्राम हुई महंगी

नयी दिल्ली : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार को तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यह पिछले चार वर्षों में पेट्रोल-डीजल के दाम में पहली वृद्धि है। कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण तेल विपणन कंपनियों का घाटा बढ़ने के बीच यह वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी की कीमतों में दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब 87.67 रुपये के मुकाबले 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। दरें राज्यों में मूल्य वर्धित कर (वैट) के अंतर के कारण अलग-अलग होती हैं। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम और मुंबई में 84 रुपये प्रति किलोग्राम है। हालांकि, घरों में खाना पकाने के लिए पाइप से मुहैया कराई जाने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और घरेलू खाना पकाने वाली गैस एलपीजी दोनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया; डीजल व एटीएफ पर कर घटाया

सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जबकि डीजल पर कर घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर कर घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया। नयी दरें 16 मई से प्रभावी होंगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा।

पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार: प्रधानमंत्री मोदी

अबू धाबी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि खाड़ी देश ने जिस तरह से संयम रखते हुए मौजूदा स्थिति को संभाला है वह प्रशंसनीय है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ अपनी मुलाकात के दौरान, मोदी ने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। पश्चिम एशिया में अस्थिर स्थिति का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, ''भारत शांति और स्थिरता की बहाली के लिए जल्द से जल्द हर संभव सहयोग देने को तैयार है।'' प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित पारगमन मार्ग और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने के पक्ष में भारत की स्पष्ट स्थिति को भी व्यक्त किया, जो कि स्थायी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के साथ-साथ ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''होर्मुज जलडमरूमध्य को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'' साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना आवश्यक है। मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच विस्तृत चर्चा हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और खाड़ी देश के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता को दोहराया।

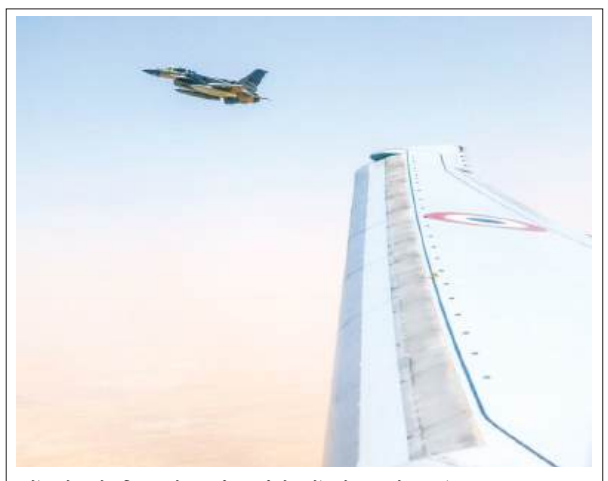

नरेंद्र मोदी के विमान के यूएई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही संयुक्त अरब अमीरात वायु सेना के एफ-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट कर स्वागत किया

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शुक्रवार को पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति, रक्षा और जहाजरानी से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अबू धाबी ने भारत में कुल पांच अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन छह समझौतों में रणनीतिक रक्षा साझेदारी से संबंधित रूपरेखा भी शामिल है, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। इसके तहत, दोनों देश कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अलावा सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए हैं।

नीट-यूजी की पुन: परीक्षा 21 जून को होगी : धर्मेंद्र प्रधान

अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी

नयी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की पुन: परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर सुधारों के तहत अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र और उनका भविष्य सरकार की ''सर्वोच्च प्राथमिकता'' हैं। उन्होंने कहा कि नीट-यूजी परीक्षा के संचालन में पाई गई अनियमितताओं के खिलाफ 'बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने' की नीति अपनाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रधान ने बताया कि पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ा दी गई है और उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार शहर चुनने का मौका फिर से मिलेगा और उन्हें 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएगा।

उन्होंने कहा, ''छात्रों का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं समाज से, विशेष रूप से छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि वे बिना किसी डर के परीक्षा दें। सरकार आपके साथ है। इस बार हम किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने देंगे।''

सीबीआई ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले के 'सरगना' को पुणे से गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) प्रश्नपत्र लीक मामले के कथित 'सरगना' एक प्रोफेसर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच शुरू होने के तीन दिन के भीतर इसे सुलझाने का दावा करते हुए पुणे के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है, जिसे प्रश्नपत्र लीक का ''मुख्य स्रोत'' बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ और लातूर निवासी प्रोफेसर पी वी कुलकर्णी कई वर्षों से नीट प्रश्नपत्र तैयार करने वाली समितियों से जुड़े रहे हैं। प्रोफेसर कुलकर्णी को पुणे स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, गोपनीय सामग्री तक विशेष पहुंच का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर कुलकर्णी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अपने घर पर विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित कीं, जिनमें उन्होंने छात्रों को वे प्रश्न, विकल्प और उत्तर लिखवाए जो तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में पूछे गए थे।

महिला सुरक्षा पर दिल्ली बार-बार शर्मसार

चौदह साल पहले दिल्ली में जिस निर्भया कांड ने भारत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था, दिल्ली में एक बार फिर उस जैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति हुई है। दिल्ली ने एक बार फिर इस भयावह सच का सामना किया किया है कि वहां की सार्वजनिक जगहें महिलाओं के लिये कितनी असुरक्षित व भयावह बनी हुई हैं। दुर्भाग्य से एक बार फिर वही बस अपराध स्थली बनी है, जो सार्वजनिक आवागमन और सुरक्षा के लिये बनी होती हैं। दिल्ली स्थित नांगलोई में एक प्राइवेट स्लीपर बस के भीतर ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा एक महिला के साथ कथित रूप से गैंगरेप की घटना ने सभ्य समाज को गहरे तक विचलित किया है। इस घटना ने एक बार फिर से शासन-प्रशासन, पुलिसिंग और परिवहन नियमों के पालन में हुई भारी चूक का एक जीता-जागता सबूत पेश किया है। निस्संदेह, इस घटना की क्रूरता केवल उस हमले में ही नहीं है, बल्कि उत्पन्न परिस्थितियों की भयानक रूप में जानी-पहचानी प्रकृति में भी है। विडंबना देखिए कि जिस बस को महिलाएं सार्वजनिक यातायात के लिये सुरक्षित मानकर चलती हैं, उसी में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। एक बार फिर बस अपराधियों के मंसूबों को पूरा करने वाला साधन बनी। इस घटना ने एक बार फिर से उजागर किया है कि जिन लोगों को यात्रियों के सुरक्षित आवागमन की जिम्मेदारी दी गई थी, वे ही कथित तौर पर दरिंदे बनकर सामने आए। हर बार की तरह तुरंत कार्रवाई का दावा करते हुए गिरफ्तारी को तत्काल कदम उठाने के रूप में दर्शाया जा रहा है। जबकि एक हकीकत है कि हमारी व्यवस्था की विद्रूपताएं जस की तस बनी हुई हैं। सही मायनों में देश के हृदय में वर्ष 2012 के जख्म अभी भरे नहीं हैं। विडंबना देखिए कि निर्भया कांड के बाद सरकारों ने तमाम सुधारों के वायदे जनता के सामने किए थे। तब घोषणा की गई थी कि अपराधियों पर नजर रखने के लिये दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को व्यापक रूप दिया गया है। लेकिन परिणाम जस के तस रहे।

देश को याद है कि वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद त्वरित फैसले लेने वाली अदालतों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा महिला सुरक्षा से जुड़ी तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये व्यापक प्रचार किया गया था। इसके बावजूद एक और निर्भया जैसी घटना बताती है कि अब तक जमीनी हकीकत में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है। देखने में आया है कि तमाम निजी बसें अपर्याप्त निगरानी व लचर सुरक्षा व्यवस्था के साथ चलती रहती हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन अक्सर महज दिखावे के लिये होता है। निस्संदेह, निजी बसों के कर्मचारियों की सख्त जांच के अभाव ने ऐसे वातावरण को तैयार किया है जहां चालक-परिचालक व अन्य अपराधियों की समांतर गुंडागर्दी चलती रहती है। यही वजह है कि गाहे-बगाहे दिल्ली की छवि महिलाओं के लिये असुरक्षित शहर होने के कारण खराब हुई है। जिसका कारण है कि यहां जवाबदेही संस्थागत होने के बजाय सतही तौर पर नजर आती है। यह विडंबना ही है कि हर बार ऐसी घटना के बाद जन आक्रोश में उबाल आता है। लेकिन देखने में आता है कि जल्दी ही राजनीतिक बयानबाजी और कालांतर नौकरशाही की उदासीनता में बदल जाता है। यही वजह है कि महिलाएं इस भय को अपनी नियति मानकर जीने को अभिशप्त हैं। दिल्ली की जागरूक जनता को चाहिए कि वे नांगलोई की घटना को महज एक और गुजरती सुर्खी बनकर न रहने दें। उन्हें इसे ऐसे अपराधों को रोकने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ बनाना चाहिए। निस्संदेह, दिल्ली के अधिकारियों को निजी परिवहन संचालकों की व्यापक जांच-पड़ताल करनी चाहिए। जिसमें रियल-टाइम जीप-ीएस ट्रैकिंग को निजी बसों में अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। साथ ही निजी बस चालक व परिचालकों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि सरकारों को समझ लेना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा महज बयानबाजी व नारे लगाने से सुनिचित नहीं होगी। साथ ही शासन-प्रशासन को घटना के बाद पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि अपराध नियंत्रण की दिशा में भी गंभीर पहल होनी चाहिए।

यूपी में ब्राह्मण वोटरों के लिये सजते सियासी गुलदस्ते

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज एक बार फिर केंद्र में आ गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगभग सभी प्रमुख दल इस समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गये हैं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार माने जाने वाले ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर अब विपक्षी दलों को यह उम्मीद दिखाई दे रही है कि उनमें कुछ नाराजगी पनप रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही अपने-अपने तरीके से ब्राह्मण समाज को साधने में लगी हुई हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी यह समझती है कि यदि ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में उससे दूर हुए तो उसका चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है। इसलिए सत्ता पक्ष भी लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार यह संदेश देने में लगे हैं कि वर्तमान सरकार में एक खास जाति का प्रभाव बढ़ गया है और ब्राह्मण समाज स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। सपा यह धारणा बनाने का प्रयास कर रही है कि प्रशासनिक तंत्र में ठाकुर समाज के अधिकारियों का दबदबा है और उन्हें बेहतर पदों पर तैनाती मिल रही है। कानून व्यवस्था से जुड़े कुछ मामलों को भी इसी दृष्टि से प्रचारित किया जा रहा है ताकि ब्राह्मण मतदाताओं के भीतर असंतोष पैदा किया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या उसका अपना पुराना इतिहास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मृतियां बहुत जल्दी धुंधली नहीं होतीं। बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता आज भी उस दौर को याद करते हैं जब सपा की सरकार पर गुंडाराज, जातीय पक्षपात और कानून व्यवस्था बिगड़ने के आरोप लगते थे। उस समय कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्हें विपक्ष ने ब्राह्मण विरोधी वातावरण के रूप में प्रचारित किया। यही वजह है कि सपा चाहे जितनी कोशिश करें, उसके सामने भरोसे का संकट बना हुआ है। स्थिति तब और कठिन हो जाती है जब पार्टी के कुछ नेता विवादित बयान दे देते हैं। सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार भाटी का हालिया बयान इसी श्रेणी में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज की तुलना अपमानजनक तरीके से की। ऐसे बयान सपा की उस कोशिश को कमजोर करते हैं, जिसमें वह स्वयं को ब्राह्मण हितैषी साबित करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल सम्मेलनों और नारों से कोई समाज प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह नेताओं की भाषा और व्यवहार को भी देखता है। यदि पार्टी के भीतर से ही विरोधाभासी संकेत मिलें तो मतदाताओं का भरोसा बन पाना कठिन हो जाता है।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी इस समय ब्राह्मण वोटरों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। एक समय ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी ने दलित और ब्राह्मण सामाजिक समीकरण के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त की थी। उस दौर में ब्राह्मण शंख बजायेगा, हाथी बढ़ता जायेगा जैसे नारे खूब चर्चित हुए थे। पार्टी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाया और उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी भी दी। हालांकि बसपा के सामने भी विरोधाभास की समस्या है। राजनीतिक विरोधियों को आज भी उसका पुराना नारा तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार याद है। विरोधी दल यह सवाल उठाते हैं कि जो पार्टी कभी ब्राह्मण विरोधी नारे लगाती थी, वह आज अचानक ब्राह्मण हितैषी कैसे बन गयी। यही कारण है कि मायावती लगातार समाजवादी पार्टी को घेरते हुए स्वयं को अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। मायावती समझती हैं कि यदि ब्राह्मण मतदाता भाजपा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें आकर्षित करने का अवसर अभी भी मौजूद है। इसलिए वह सपा पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से अपने नेताओं के बयानों पर माफी मांगने की मांग कर रही हैं। यह केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। बसपा चाहती है कि ब्राह्मण समाज के भीतर यह संदेश जाए कि सपा केवल चुनावी लाभ के लिए उन्हें याद कर रही है, जबकि उसके नेताओं की मानसिकता अब भी वही है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देख रहे हैं। भाजपा की राजनीति लंबे समय से सामाजिक संतुलन पर आधारित रही है। पार्टी यह भलीभांति जानती है कि उत्तर प्रदेश में केवल एक जाति के सहारे सत्ता में बने रहना संभव नहीं है। ब्राह्मण समाज भाजपा का परंपरागत समर्थक माना जाता रहा है और यदि उसमें नाराजगी का संदेश फैलता है तो उसका असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। इसी कारण हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मण चेहरे मनोज पाण्डेय को मंत्री बनाकर भाजपा ने स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि सरकार में ब्राह्मण समाज की भागीदारी और सम्मान दोनों सुरक्षित हैं। इसके अलावा पार्टी संगठन में भी ब्राह्मण नेताओं की सक्रियता बढ़ायी जा रही है। भाजपा की चिंता यह है कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि वर्तमान सरकार में ठाकुर समाज का प्रभाव अधिक है। कई प्रशासनिक नियुक्तियों और पुलिस कार्यवाहियों को लेकर भी सवाल उठाये गये हैं। लेकिन भाजपा समर्थकों का कहना है कि योगी सरकार ने जाति के बजाय कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बिना भेदभाव के की गयी है। भाजपा का तर्क यह भी है कि यदि केवल जातीय आधार पर शासन चल रहा होता तो उसे लगातार व्यापक जनसमर्थन नहीं मिलता।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को लेकर तीनों प्रमुख दलों में रस्साकशी इसलिये हो रही है क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या भले ही बहुत अधिक न हो, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है। यह समाज केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक और वैचारिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि हर दल उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह किसी एक दल के साथ बंधा हुआ नहीं दिख रहा। वह अपने सम्मान, भागीदारी और सुरक्षा को लेकर सजग है। लेकिन साथ ही वह पुराने अनुभवों को भी याद रखता है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वह केवल आरोपों के सहारे नहीं, बल्कि व्यवहार और नेतृत्व की विश्वसनीयता के माध्यम से भरोसा पैदा करे। बहुजन समाज पार्टी को अपने पुराने नारों और छवि से बाहर निकलना होगा। वहीं भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके खिलाफ फैलाई जा रही उपेक्षा की धारणा मजबूत न हो। कुल मिलाकर, 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव केवल विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होगा, बल्कि सामाजिक संतुलन और राजनीतिक विश्वास की भी परीक्षा बनेगा। ब्राह्मण मतदाता इस बार किस ओर जायेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता उसके रुख से जरूर प्रभावित होगा। सभी दलों के नेताओं ने ब्राह्मण वोटों के लिये सियासी गुलदस्ते तैयार कर रखे हैं। देखना यह है कि 2027 में ब्राह्मण वोटर किसका गुलदस्ता स्वीकार करेगा।

-वरिष्ठ पत्रकार

भोजशाला निर्णय: अदालत ने आस्था नहीं, रिकॉर्ड और प्रमाण को आधार बनाया

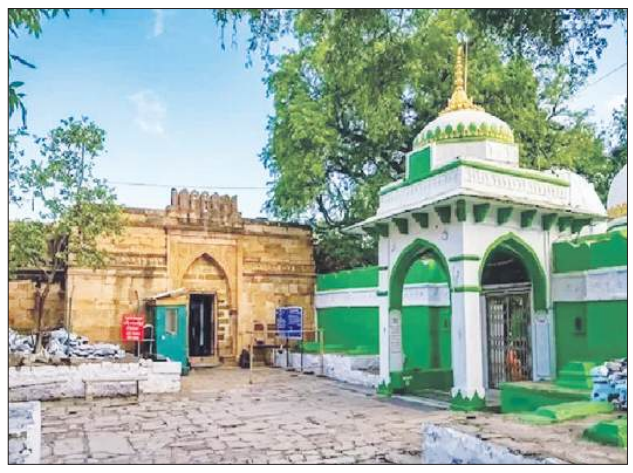

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर ने 15 मई 2026 को धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर से जुड़े लंबे विवाद पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह मामला केवल पूजा या नमाज़ की अनुमति का नहीं था। असली प्रश्न यह था कि इस विवादित परिसर का धार्मिक और ऐतिहासिक चरित्र क्या है। एक पक्ष का कहना था कि यह स्थान भोजशाला है, माँ वाग्देवी अर्थात माँ सरस्वती का मंदिर है और संस्कृत अध्ययन की प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। दूसरे पक्ष का कहना था कि यह कमाल मौला मस्जिद है और मुस्लिम समुदाय को वहाँ नमाज़ का अधिकार है। अदालत ने इस विवाद को केवल भावनाओं या दावों के आधार पर नहीं देखा। उसने पुरातात्त्विक सर्वेक्षण, शिलालेखों, स्थापत्य, पुराने सरकारी अभिलेखों, ऐतिहासिक सामग्री और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया।

भोजशाला का ऐतिहासिक संदर्भ

निर्णय में दर्ज सामग्री के अनुसार भोजशाला का संबंध परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज से जोड़ा गया। राजा भोज को विद्या, संस्कृत, व्याकरण, ज्योतिष, खगोलशास्त्र और शास्त्रों का संरक्षक बताया गया। याचिकाकर्ताओं का पक्ष था कि यह स्थान केवल भवन नहीं, बल्कि संस्कृत शिक्षा और माँ वाग्देवी की उपासना का केंद्र था। अदालत ने इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एएसआई रिपोर्ट, शिलालेखों और स्थापत्य सामग्री के साथ पढ़ा। अदालत ने पाया कि यह मामला केवल नाम का नहीं, बल्कि उस स्थान के वास्तविक चरित्र का है।

एएसआई सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण रहा

इस मामले में एएसआई की दस खंडों वाली रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण रही। न्यायालय के निर्देश पर वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन किया गया। अदालत ने इस रिपोर्ट को विस्तार से देखा। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान संरचना के नीचे एक पूर्ववर्ती बड़ी संरचना मिली, जिसका संबंध परमार काल, अर्थात लगभग दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से बताया गया। यह संरचना ईंटों से बनी थी और बाद में बेसाल्ट पत्थर से विस्तारित हुई। रिपोर्ट में 94 मूर्तियों और खंडों का उल्लेख है। इनमें गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव, कीर्तिमुख, पशु आकृतियाँ और पौराणिक आकृतियाँ शामिल बताई गईं। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी मानव और पशु आकृतियाँ सामान्य मस्जिद संरचना से मेल नहीं खातीं। कई आकृतियों को विकृत या क्षतिग्रस्त भी पाया गया। एएसआई रिपोर्ट में 106 स्तंभ और 82 उपस्तंभों का उल्लेख आया। इनमें अनेक स्तंभ मंदिर शैली के बताए गए, जिनका बाद की संरचना में पुनः उपयोग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शिलालेखों से जुड़ा था। रिपोर्ट में 150 से अधिक संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों का उल्लेख है। अदालत ने यह भी देखा कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेख, अरबी और फारसी शिलालेखों से पुराने हैं। अदालत ने माना कि ये सभी तथ्य मिलकर यह संकेत देते हैं कि यह स्थान पहले संस्कृत अध्ययन, धार्मिक गतिविधि और माँ वाग्देवी/सरस्वती की परंपरा से जुड़ा हुआ था।

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा

मुस्लिम पक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण आपत्तियाँ उठाई गईं। पहली आपत्ति यह थी कि यह मामला रिट याचिका में तय नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विवादित तथ्य, स्वामित्व, कब्जा और ऐतिहासिक दावे शामिल हैं। उनके अनुसार पक्षकारों को दीवानी वाद में जाना चाहिए। दूसरी आपत्ति यह थी कि 7 अप्रैल 2003 का एएसआई आदेश बहुत पहले पारित हुआ था, इसलिए इतने वर्षों बाद याचिका विलंब के कारण खारिज होनी चाहिए। तीसरी आपत्ति यह थी कि पहले भी इस संबंध में मुकदमे और कार्यवाहियाँ हो चुकी हैं, इसलिए वर्तमान मामला पुनः नहीं खोला जाना चाहिए। चौथी आपत्ति पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और वक्फ से जुड़ी थी। मुस्लिम पक्ष ने 1935 के धार राज्य के एलान, 1985 की राजपत्र अधिसूचना, वक्फ पंजीकरण, शुक्रवार की नमाज़ और पुराने सरकारी अभिलेखों पर भरोसा किया। पाँचवीं आपत्ति एएसआई सर्वेक्षण पर थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वेक्षण की पद्धति, उत्खनन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और वैज्ञानिक जांच को लेकर गंभीर प्रश्न हैं।

मुस्लिम पक्ष की दलीलें क्यों स्वीकार नहीं हुईं

अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर विस्तार से विचार किया, लेकिन उन्हें अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले, अदालत ने कहा कि यह मामला स्वामित्व घोषित करने का नहीं है। यह पूजा-अधिकार और संरक्षित स्मारक के धार्मिक चरित्र से जुड़ा मामला है। इसलिए केवल यह कहकर याचिका खारिज नहीं की जा सकती कि इसमें विवादित तथ्य हैं। अदालत ने अनुच्छेद 226 के व्यापक अधिकार क्षेत्र पर भरोसा किया और माना कि जहाँ पूजा के मूल अधिकार और संवैधानिक प्रश्न जुड़े हों, वहाँ उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। विलंब की दलील भी स्वीकार नहीं हुई। अदालत ने कहा कि 7 अप्रैल 2003 का एएसआई आदेश अभी भी प्रभावी था और उसके कारण पूजा-अधिकारों पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए यह निरंतर कारण-कार्रवाई का मामला माना गया। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की आपत्ति भी अस्वीकार हुई। अदालत ने माना कि विवादित क्षेत्र 1958 के प्राचीन स्मारक अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है। पूजा स्थल अधिनियम की धारा 4(3) में ऐसे संरक्षित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को अलग स्थिति दी गई है। इसलिए इस आधार पर याचिकाएँ बाधित नहीं मानी गईं। वक्फ से जुड़े दावे पर भी अदालत ने कहा कि भूमि क्रमांक 604, पुराना क्रमांक 313, के किसी भाग को वक्फ संपत्ति मानने या विधिवत समर्पित किए जाने का पर्याप्त पदार्थ रिकॉर्ड पर नहीं है। अदालत ने माना कि केवल पुराने उल्लेखों, राजपत्र या सरकारी वर्णन से अपने आप मस्जिद का अंतिम अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एएसआई सर्वेक्षण पर उठाई गई आपत्तियों को भी अदालत ने स्वीकार नहीं किया। अदालत ने वीडियोग्राफी और आपत्तियों पर विचार करने के बाद पाया कि सर्वेक्षण निष्पक्ष और वैज्ञानिक पद्धति से किया गया। अदालत ने यह भी माना कि सर्वेक्षण दल में वरिष्ठ विशेषज्ञ थे, दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और सामग्री का दस्तावेजीकरण किया गया था। कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर अदालत ने एएसआई के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया कि कार्बन डेटिंग वस्तु की सामग्री की उम्र बताती है, निर्माण की अवधि नहीं। इसलिए वास्तु संरचना की अवधि समझने के लिए शैलीगत, पुरातात्त्विक और वैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग किया गया।इन्हीं कारणों से अदालत ने मुस्लिम पक्ष की यह बात स्वीकार नहीं की कि विवादित क्षेत्र को केवल मस्जिद के रूप में माना जाए।

अदालत का मुख्य निष्कर्ष

अदालत ने पुरातात्त्विक सामग्री, ऐतिहासिक साहित्य, एएसआई अधिसूचनाएँ, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और वैधानिक प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया। अदालत ने कहा कि विवादित क्षेत्र भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद 1958 के अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है और इसका दर्जा 18 मार्च 1904 से माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि विवादित क्षेत्र का धार्मिक चरित्र - माँ वाग्देवी अर्थात सरस्वती के मंदिर सहित भोजशाला है। इसका अर्थ यह है कि अदालत ने रिकॉर्ड और एएसआई सर्वेक्षण के आधार पर भोजशाला को माँ वाग्देवी/माँ सरस्वती की मंदिर-परंपरा और संस्कृत अध्ययन केंद्र से जुड़ा माना।

2003 के एएसआई आदेश का क्या हुआ

7 अप्रैल 2003 के एएसआई आदेश के कारण हिंदू समुदाय की पूजा सीमित थी और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज़ की अनुमति थी। अदालत ने इस आदेश को उस सीमा तक निरस्त कर दिया, जहाँ वह भोजशाला परिसर में हिंदुओं के पूजा-अधिकार को सीमित करता था और मुस्लिम समुदाय को वहाँ प्रार्थना की अनुमति देता था। साथ ही अदालत ने भारत सरकार और एएसआई को भोजशाला मंदिर तथा संस्कृत अध्ययन की प्रशासनिक और प्रबंधन व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने को कहा। एएसआई को संरक्षण, संवर्धन और धार्मिक प्रवेश के नियमन पर संपूर्ण पर्यवेक्षण नियंत्रण दिया गया।

मुस्लिम समुदाय के लिए संतुलन

निर्णय का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि अदालत ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गरिमा को अनदेखा नहीं किया। अदालत ने कहा कि यदि संबंधित मुस्लिम पक्ष धार जिले में मस्जिद या प्रार्थना-स्थल के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन देता है, तो राज्य सरकार कानून के अनुसार उस पर विचार कर सकती है। यह बात निर्णय में संवैधानिक संतुलन को दर्शाती है।

इस निर्णय की अलग बात

इस निर्णय की पहली विशेषता यह है कि अदालत ने इसे केवल आस्था बनाम आस्था का विवाद नहीं माना। अदालत ने आस्था को रिकॉर्ड, पुरातत्व, शिलालेख और वैधानिक कर्तव्य की कसौटी पर परखा। दूसरी विशेषता यह है कि अदालत ने एएसआई को केवल स्मारक का रखवाला नहीं माना। अदालत ने कहा कि संरक्षित स्मारक की शुद्धता, संरक्षण, संवर्धन और धार्मिक प्रवेश का नियमन भी एएसआई की जिम्मेदारी है। तीसरी विशेषता यह है कि अदालत ने पुराने सरकारी अभिलेखों को अंतिम सत्य नहीं माना। उसने कहा कि उन्हें पुरातात्त्विक सामग्री, शिलालेख, संरचना, पूजा की निरंतरता और अन्य परिस्थितियों के साथ पढ़ना होगा। चौथी विशेषता यह है कि जैन पक्ष के दावे पर भी अदालत ने विचार किया। जैन पक्ष ने अंबिका और जैन विरासत का दावा किया था, लेकिन अदालत ने माना कि विवादित क्षेत्र को जैन मंदिर घोषित करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक, स्थापत्य या एएसआई सर्वेक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसलिए जैन याचिका खारिज हुई।

निष्कर्ष

भोजशाला निर्णय में अदालत ने भावनाओं से अधिक रिकॉर्ड को महत्व दिया। एएसआई रिपोर्ट, शिलालेख, स्थापत्य, ऐतिहासिक सामग्री और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर अदालत ने विवादित क्षेत्र का धार्मिक चरित्र माँ वाग्देवी अर्थात सरस्वती के मंदिर सहित भोजशाला माना। यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों में केवल दावा पर्याप्त नहीं होता। प्रमाण, रिकॉर्ड, पुरातत्व और वैधानिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

(विकास धनानिया)

आज का पंचांग

कोलकाता : 16 मई, शनिवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2083, ज्येष्ठ कृष्णपक्ष अमावस्या, 25:29 तक, नक्षत्र : भरणी, 17:27 तक, योग : सौभाग्य, 10:23 तक, सूर्योदय: 04:56, सूर्यास्त: 18:09, चन्द्रोदय : 04:41, चन्द्रास्त: 18:26, शक सम्वत: 1948 पराभव, सूर्य राशि : वृषभ, चन्द्र राशि : मेष, राहू काल : 08:54 से 10:32

राशिफल

मेष : आज का दिन आपके लिए खास उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है। लंबे समय से अटका कोई जरूरी काम आखिरकार पूरा हो सकता है। परिवार में एकजुटता बनी रहेगी।

वृष : आज का दिन सामान्य होते हुए भी कई नए अवसर लेकर आ सकता है। नई नौकरी का ऑफर आकर्षित करेगा, लेकिन फिलहाल पुरानी जगह टिके रहना समझदारी होगी।

मिथुन : आज का दिन सामान्य होते हुए भी कई नए अवसर लेकर आ सकता है। नई नौकरी का ऑफर आकर्षित करेगा, लेकिन फिलहाल पुरानी जगह टिके रहना समझदारी होगी।

कर्क : आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभल जाएगी।

सिंह : आज भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। बिजनेस में नई पार्टनरशिप भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उधार लेने से बचें।

कन्या : आज जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोकप्रियता और जनसमर्थन बढ़ेगा।

तुला : आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। आय और खर्च के बीच तालमेल ही आपकी शांति बनाए रखेगा। परिवार की समस्याओं में बाहरी लोगों की सलाह लेने से बचें।

वृश्चिक : आज का दिन खुशियों और नए बदलावों से भरा रह सकता है। दूर रहने वाले किसी प्रियजन से मुलाकात मन को सुकून देगी। घर की सजावट या रिनोवेशन पर खर्च बढ़ सकता है।

धनु : आज तरक्की के नए रास्ते आपके सामने खुल सकते हैं। बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना सफल हो सकती है। दोस्तों के साथ बिताया गया समय तनाव कम करेगा।

मकर : आज उन्नति की रफ्तार तेज रहने वाली है। आपकी मेहनत और तेजी से किए गए काम कुछ लोगों को परेशान कर सकते हैं, जिससे नए विरोधी भी बन सकते हैं।

कुम्भ : आज का दिन बाकी दिनों से ज्यादा खुशनुमा और सुकून भरा रहेगा। घर-परिवार में खुशी और एकता का माहौल बना रहेगा। संतान की परीक्षा का परिणाम मन को राहत देगा।

मीन : आज थोड़ी सावधानी और समझदारी की जरूरत रहेगी। छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी से बहस होने की संभावना है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें।

वर्ग पहेली नं. 3440

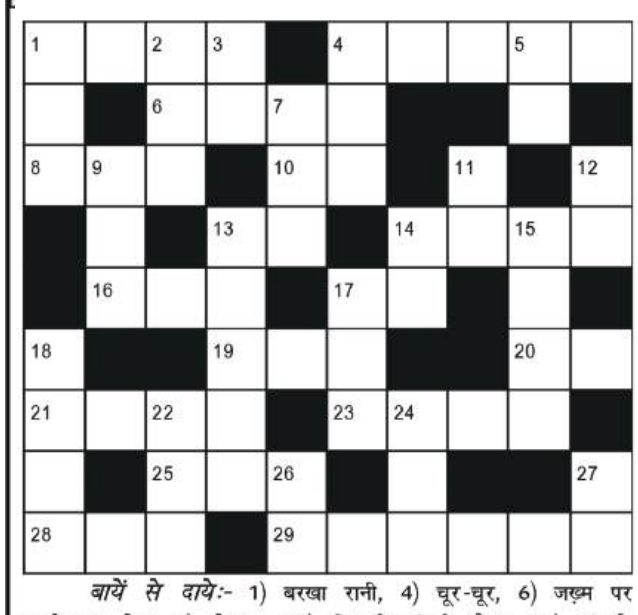

ऊपर से नीचे:- 1) पास, 2) मुक़ाबला, 3) गीला, 4) कांति, 5) एक घरेलू जंतु, 7) जीवन, 9) घड़ा, 11) टाट का बना थैला, 12) ख़्याल; ध्यान, 13) हितैषी, 14) स्कूली बच्चों का थैला, 15) वृद्धि, 17) जीता, 18) संदेह, 22) कठिन, 24) नमी, 26) थूक, 27) घृणा. *(उत्तर: अगले अंक में)*

बायें से दायें:- 1) बरखा रानी, 4) चूर-चूर, 6) जख़्म पर लगाने का लेप, 8) पोतना, 10) तिब्बती जंगली भैंसा, 13) भलाई, 14) समान, 16) के बिना, 17) सहँगा; कम ख़र्चीला, 19) अफ़्रीकी अपिवानर, 20) अंकुर, 21) बे-मेल, 23) मृत्युपत्र, 25) रुक रुककर बोलनेवाला, 28) मान-प्रतिष्ठा से युक्त, 29) तौर तरीक़ा; जीवनस्तर.

पिछली पहेली का उत्तर

त	■	प	रि	चा	र	क	■	ज्ञा	प
ला	■	र	क्त	■	सी	■	जि	र	ह
क़	री	ना	■	औ	ला	द	■	दा	ल
शु	■	ना	टा	■	प	ल	क	■	वा
दा	न	■	य	क़ी	न	■	व	त	न
■	दा	य	र	■	■	सू	च	ना	■
औ	र	■	■	आ	चा	र्य	■	व	फ़ा
स	द	स	द्धि	वे	क	■	प्रा	■	ज़ि
त	■	न्न	■	श	र	णा	र्थी	■	ल

Mob. No. 08329510310

सुडोकू-पहेली-3398

4								1
	9					6		
7	2			8	1	5		
			2					
8		1		7	5		2	
						8	9	
2	8			4			7	
6					2			
		3						

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

••••

आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3397 का उत्तर

3	8	5	9	4	2	1	6	7
4	2	7	1	6	5	8	9	3
9	1	6	8	3	7	2	4	5
1	3	2	4	5	6	7	8	9
5	4	9	7	2	8	6	3	1
7	6	8	3	1	9	5	2	4
6	9	1	5	8	3	4	7	2
8	5	3	2	7	4	9	1	6
2	7	4	6	9	1	3	5	8

राज्य में चुनाव बाद हिंसा की कोई जानकारी नहीं, सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी : मुख्यमंत्री

❑ **नेता प्रतिपक्ष शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने चुनाव बाद हिंसा के कारण कई लोगों के बेघर होने का लगाया आरोप**

❑ **भाजपा विधायकों ने सदन में लगाए चोर-चोर के नारे, तृणमूल ने किया सदन से वाकआउट**

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी तृणमूल कांग्रेस द्वारा चुनाव बाद हिंसा के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है और इस बात पर बल दिया कि ऐसे आरोपों के सही तरीके से सत्यापन के बाद ही कार्रवाई होगी। दरअसल, वह विधानसभा में विपक्ष के नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय द्वारा चुनाव बाद हुई हिंसा के आरोपों का जवाब दे रहे थे। नवगठित विधानसभा के पहले सत्र के दौरान चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के बाद राज्यभर में हिंसा के कारण कई लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। तृणमूल के विधायक ने सदन में कहा कि कई जगहों पर हिंसा हो रही है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके जवाब में, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। अगर कोई बेघर हुआ तो पुलिस और प्रशासन उनकी वापसी कराएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी वास्तविक मामलों में कानून अपना काम करेगा। सदन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब भाजपा विधायकों ने 'चोर चोर' के नारे लगाए, जिसके बाद तृणमूल ने कुछ देर के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। तृणमूल के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी सदन से अनुपस्थित रहे, हालांकि बाद में वापस लौट आए।

❑ **'हम सकारात्मक विपक्ष चाहते हैं, विधानसभा टकराव की जगह नहीं', विपक्ष को मिलेगा 50% समय**

विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद नवगठित 18वीं विधानसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि यह सदन 'जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने' में अहम भूमिका निभाएगा और संवैधानिक सिद्धांतों तथा स्थापित नियमों के अनुसार काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम संविधान को ध्यान में रखकर विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। सदन में 'मजबूत और सकारात्मक विपक्ष' की जरूरत पर बल देते हुए अधिकारी ने कहा कि हम सकारात्मक विपक्ष चाहते हैं। विधानसभा टकराव की जगह नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से यह सदन विपक्ष का है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में बोलने का समय 50-50 के आधार पर होगा। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी विधायक को निलंबन की कार्रवाई का सामना करना पड़े और सदन की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

❑ **'हर पत्र का मिलेगा जवाब, संवाद के लिए दरवाजे खुले रहेंगे', मुख्यमंत्री का विपक्ष को संदेश**

विधानसभा में स्पीकर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी विधायकों, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस सदस्यों के लिए विशेष संदेश देते हुए कहा कि उनकी सरकार संवाद और जवाबदेही की नीति पर काम करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब विपक्ष के पत्रों का जवाब मिलेगा और समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया जाएगा। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हाउस बिलॉन्ग्स टू ऑपोजिशन' की भावना को आधार बनाकर सदन की कार्यवाही चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संख्या में आप लोग कम हैं, लेकिन हम सदन को 50-50 की भावना से चलाना चाहते हैं। हमारी संख्या अधिक होने के बावजूद हम चाहेंगे कि स्पीकर विपक्ष को अधिक बोलने का अवसर दें। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों को मंत्रियों से मिलने और अपनी समस्याएं रखने का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि यदि आपकी पार्टी अनुमति दे, तो आप मंत्रीगण से मिल सकते हैं। हम मंत्रियों से भी कहेंगे कि वे मिलने के लिए समय दें। आवश्यकता पड़ने पर आप पत्र भेज सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकार पर परोक्ष हमला बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले कई मंत्री विपक्ष के पत्रों का जवाब नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तो जवाब की उम्मीद ही नहीं की जाती थी। लेकिन हमारी सरकार में यदि कोई पत्र आएगा, तो उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। केवल प्राप्ति स्वीकार ही नहीं, बल्कि सकारात्मक समाधान का प्रयास भी होगा।

❑ **सदन में रचनात्मक भूमिका निभाएंगे : नौशाद सिद्दीकी**

इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) विधायक नौसाद सिद्दीकी ने कहा कि पिछले चुनावों के बाद हुई हिंसा ने लोगों में भय पैदा किया था और उस समय विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया था। उन्होंने सरकार से अपील की कि विपक्षी दलों को सदन में सम्मान दिया जाए और जनता के मुद्दे उठाने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे सदन में रचनात्मक भूमिका निभाएंगे, न कि महज विरोध की राजनीति करेंगे।

भाजपा विधायक रथिंद्र बोस विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए

कोलकाता, समाज्ञा : भाजपा से विधायक रथिंद्र बोस शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। वह राज्य के उत्तरी भाग से इस पद को संभालने वाले पहले विधायक बन गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 'प्रोटेम स्पीकर' (अस्थायी अध्यक्ष) तापस रॉय ने ध्वनि मत से मतदान कराया। सभी 207 भाजपा विधायकों द्वारा बोस के पक्ष में अपना समर्थन देने के बाद अस्थायी अध्यक्ष ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गत गुरुवार को कूचबिहार दक्षिण से विधायक बोस को नवगठित 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा उम्मीदवार घोषित किया, जबकि विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। बोस के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सदन को संबोधित किया। विपक्ष के नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने भी नए विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए सदन को संबोधित किया।

विधानसभा की कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण : मुख्यमंत्री शुभेंदु

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि आम लोग जान सकें कि सदन के भीतर क्या हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद नवगठित 18वीं विधानसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सदन 'जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने' में अहम भूमिका निभाएगा और संवैधानिक सिद्धांतों तथा स्थापित नियमों के अनुसार काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम संविधान को ध्यान में रखकर विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने सदन में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से दिया इस्तीफा

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहने का विकल्प चुना। सूत्रों के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा नियमों के तहत निर्धारित अनिवार्य 14 दिनों की अवधि के भीतर विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को एक सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु ने कहा कि नंदीग्राम मेरे दिल में है। नंदीग्राम के लोगों को मैं कभी भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु ने पश्चिम बंगाल में परिसीमन का संकेत दिया

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राज्य में परिसीमन की संभावना की ओर संकेत देते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ सकती है, जिसके लिए एक नए विधानसभा भवन के निर्माण की आवश्यकता होगी। रथिंद्र बोस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद विधानसभा में अधिकारी ने ये टिप्पणियां कीं। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में विधानसभा के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलावों की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कई सुधारों की आवश्यकता है। आज यहां उपस्थित राज्य सरकार के अधिकारी इस ऐतिहासिक सत्र के साक्षी हैं। परिसीमन होने पर विधानसभा सीटों की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में हमें एक नए विधानसभा भवन का निर्माण करना पड़ सकता है। अधिकारी की टिप्पणियों ने इस बात को लेकर भी अटकलें तेज कर दी हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में भी अंततः 2023 में असम में किए गए परिसीमन की तरह ही परिसीमन हो सकता है।

भड़काऊ भाषण देने का आरोप... अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कोलकाता, समाज्ञा : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की है। राज्य पुलिस ने राजीव सरकार नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन 5 मई को राजीव सरकार ने बागुईआटी थाने में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए थे। डीजे बजाने की बात कही थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमकी दी थी। उन्होंने कई जगहों पर अभिषेक के भाषणों के लिंक जमा किए हैं। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

बंगाल विधानसभा का बजट सत्र 18 जून से होगा शुरू, पूर्ण बजट 22 जून को होगा पेश

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 जून से शुरू होगा और राज्य का पूर्ण बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य में भाजपा की नयी सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, इस बजट को पेश करेंगे। चूंकि, राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे, इसलिये पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने परंपरा के अनुसार फरवरी में लेखानुदान पेश किया था। यह अंतरिम व्यवस्था चार महीने की अवधि के लिए वैध थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब पूर्ण बजट पेश होने वाला है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने कहा कि सभी विभागों को नयी सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और प्रमुख कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ऋण पर लगाम लगाने के साथ-साथ अवसंरचना क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि दीर्घकालिक परिसंपत्तियां तैयार की जा सकें। बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल इस संबंध में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहले ही बैठक कर चुके हैं।

'पश्चिम बंगाल श्राप मुक्त, पाप मुक्त और भय मुक्त हो गया', विधानसभा में बोले तापस राय

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा में शुक्रवार को स्पीकर चुनाव के बाद हुई चर्चा के दौरान मानिकतला से भाजपा विधायक तापस राय ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब श्रापमुक्त, पापमुक्त और भयमुक्त हो गया है। चुनाव बाद हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने बिना नाम लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया। विधानसभा में भाजपा विधायक रथींद्र बोस के स्पीकर चुने जाने के बाद विभिन्न दलों के विधायक अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान तापस राय ने अपने संबोधन में तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यह केवल सरकार बनाने या चुनाव जीतने का चुनाव नहीं था, बल्कि धर्मयुद्ध था। इस धर्मयुद्ध में जीतकर आने वालों को मैं बधाई देता हूं। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने तृणमूल विधायकों की ओर देखते हुए कहा कि बहुत कुछ कर चुके हैं, अब देखने में बुरा लग रहा है क्या? इसके बाद, उन्होंने सदन में राष्ट्रविरोधी और देशविरोधी नारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने स्पीकर से कहा कि जरूरत पड़े तो इसके लिए कानून लाया जाए। तापस राय के इस बयान पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को मेज थपथपाकर समर्थन किया। तृणमूल सरकार पर हमला बोलते हुए तापस राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब श्रापमुक्त, पापमुक्त और भयमुक्त हो गया है। उन्होंने चुनाव बाद हिंसा के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि तृणमूल फिर सत्ता में लौटती, तो भाजपा के 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो सकती थी और लाखों समर्थकों को घर छोड़ना पड़ता। बिना नाम लिए अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए तापस राय ने कहा कि एक अखिल भारतीय पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव ने भाजपा उम्मीदवारों को धमकी दी थी कि उनकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। तृणमूल विधायकों के विरोध के बीच उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब वह बाहर निकलकर देखें। भाजपा कुछ नहीं करेगी, जनता और तृणमूल ही उसका हिसाब करेगी। तापस राय ने यह भी कहा कि अगर 2021 के चुनाव बाद हिंसा में उनका नाम शामिल हो, तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि वह किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थे।

मुख्यमंत्री ने 5 पश्चिमी जिलों के प्रशासन के साथ बैठक बुलाई, विकास रिपोर्ट मांगी

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जिला स्तर पर विकास की देखरेख के लिए पहली बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री 21 मई को पश्चिमी क्षेत्र के पांच जिला अधिकारियों की बैठक करेंगे। यह बैठक पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्दवान, बीरभूम और पूर्व बर्दवान जिलों के साथ होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने पांचों जिला प्रशासन को बैठक के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, इन जिलों के प्रशासन ने अंदरूनी बैठक तैयारी शुरू कर दी है। बैठक के लिए बुलाए गए 5 जिलों में किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है? उन प्रोजेक्ट्स का क्या स्टेटस है? कौन से काम धीरे चल रहे हैं? हर चीज को एक रिपोर्ट के तौर पर बैठक में पेश करने को कहा गया है। जिला प्रशासन आज से इन पांच जिलों के नए विधायकों के साथ बैठक करेगा। जिला प्रशासन को उन कामों की लिस्ट भी तैयार करने को कहा गया है जो विधायक प्रपोज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खर्च और समय बचाने के लिए 5 जिलों को एक साथ बुलाया गया है।

आज मुख्यमंत्री का डायमंड हार्बर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज दोपहर 1 बजे डायमंड हार्बर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, बैठक की सही जगह बाद में बताई जाएगी। माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों पर जरूरी बातचीत हो सकती है। भाजपा पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इसके साथ ही शुभेंदु आज फलता विधानसभा चुनाव के लिए वर्किंग बैठक करेंगे। वर्किंग मीटिंग दोपहर 3 बजे से होगी।

तृणमूल संसदीय दल में फेरबदल के बाद काकोली घोष का फूटा गुस्सा

कोलकाता, समाज्ञा

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से हटाए जाने के बाद बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी टिप्पणी को पार्टी नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी और निराशा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। काकोली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1976 में परिचय हुआ, 1984 में राजनीतिक सफर शुरू हुआ। चार दशक की निष्ठा का आज पुरस्कार मिला। काकोली ने 1976 के छात्र राजनीति के दिनों और 1984 के ऐतिहासिक चुनावों का जिक्र करते हुए अपनी और ममता बनर्जी की लंबी यात्रा को याद किया।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या: सीएलडब्ल्यू-डीकेएई-415-इलेक्ट्र-26. भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: **क्रम संख्या: |01|। निविदा सूचना संख्या: सीएलडब्ल्यू-डीकेएई-415-इलेक्ट्र-26। कार्य का नाम** : व्यापक रखरखाव, निवारक और ब्रेकडाउन दोनों (i) 03 (तीन) संख्या 33 केवी / 415 वी विद्युत सबस्टेशनों के लिए और (ii) संपूर्ण कारखाने के सामान्य विद्युत उपकरण, जिसमें बोगी शॉप और 5 (पांच) क्वार्टर ब्लॉक, टाइप-II और टाइप-III क्वार्टर और अधिकारियों के लिए ट्रांजिट आवास शामिल हैं, और आवश्यकतानुसार डीएलडब्ल्यू के सीएलडब्ल्यू, डांकुनी में दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिस्थापन 2 (दो) वर्षों के लिए किया जाएगा। **निविदा मूल्य (रुपये):** ₹ 97,68,469.72 (सत्तानवे लाख अड़सठ हजार चार सौ उनहत्तर रुपये और बहत्तर पैसे) मात्र। **निविदा दस्तावेज़ की लागत (रुपये):** ₹ 5,000.00 (केवल पाँच हज़ार रुपये)। **बयाना राशि/ बोली सुरक्षा (रुपये):** ₹ 1,95,400.00 (एक लाख पचानवे हज़ार चार सौ रुपये) मात्र। **पूरा होने की अवधि:** 24 (चौबीस) महीने। **नोट:** (i) पूरी जानकारी रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। (ii) **संपर्क नंबर: 03212-230003**। (iii) **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 01.06.2026 को 12:00 बजे है।**

PR5/349 एईई/योजना/डांकुनी

www.facebook.com/clwrailways पर हमसे जुड़ें

हावड़ा-राजगीर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव और संशोधित गठन

यात्रियों की सुविधा के लिए, **03029/03030 हावड़ा-राजगीर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन** कहलगांव स्टेशन पर निम्नलिखित समयसूची के अनुसार अतिरिक्त ठहराव प्रदान करेगी :

ट्रेन नं. और नाम	कहलगांव में समयसूची	
	आ.	प्र.
03029 हावड़ा-राजगीर एक्सप्रेस [यात्रा शुरू होने की प्रभावी तिथि 16.05.2026]	05.53	05.55
03030 राजगीर-हावड़ा एक्सप्रेस [यात्रा शुरू होने की प्रभावी तिथि 17.05.2026]	20.25	20.27

03029/03030 हावड़ा-राजगीर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन का संशोधित गठन: एसी 3-टियर - 01, शयनयान श्रेणी - 04, साधारण द्वितीय श्रेणी - 07, एसएलआरडी-02, कुल = 14 कोच।

अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

सियालदह मंडल के तहत नई लोकल ट्रेन का शुभारम्भ एवं ट्रेन सेवा का विस्तार

कनेक्टिविटी में सुधार, अत्यंत भीड़ से राहत दिलाने तथा यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए, **दिनांक 18.05.2026 से 31776 डाउन कृष्णपुर-काशिमबाजार लोकल** ट्रेन की यात्रा **बहरमपुर कोर्ट** तक विस्तार की जाएगी तथा बहरमपुर कोर्ट से लालगोला तक एक नई ईएमयू लोकल ट्रेन सेवा अर्थात् **31777 अप बहरमपुर कोर्ट-लालगोला लोकल ट्रेन** का शुभारम्भ किया जाएगा। विस्तार के उपरांत तथा नई ट्रेन की विस्तृत समय-सूची निम्नानुसार होगी:-

सेवा का विस्तार — **विस्तारित 31776 डाउन कृष्णपुर-बहरमपुर कोर्ट लोकल ट्रेन की समय-सूची:-**

स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
कृष्णपुर	↓ -	06.55
पीरतला	07.00	07.01
भगवानगोला	07.05	07.06
सुवर्णमृगी	07.12	07.13
जियागंज	07.18	07.19
मुर्शिदाबाद	07.26	07.27
काशिमबाजार	**07.33**	**07.34**
बहरमपुर कोर्ट	**07.47**	-

नई ट्रेन सेवा — **31777 अप बहरमपुर कोर्ट-लालगोला लोकल ट्रेन की समय-सूची:-**

आगमन	आगमन	प्रस्थान
बहरमपुर कोर्ट	↓ -	08.35
काशिमबाजार	08.39	08.40
मुर्शिदाबाद	08.46	08.47
जियागंज	08.54	08.55
सुवर्णमृगी	09.00	09.01
भगवानगोला	09.07	09.08
पीरतला	09.12	09.13
कृष्णपुर	09.21	09.22
लालगोला	09.35	-

मंडल रेल प्रबंधक, सियालदह

पूर्व रेलवे

हमें अनुसरण करें @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पुरी-पटना-पुरी एक्सप्रेस की शुरुआत

08439/08440 पुरी - पटना - पुरी स्पेशल ट्रेन के नियमित होने के बाद पुरी और पटना के बीच एक नई ट्रेन, अर्थात 18405/18406 **पुरी - पटना - पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस** शुरू की जाएगी। 18405 **पुरी - पटना एक्सप्रेस** की सेवा **दिनांक** 23.05.2026 **(शनिवार)** से शुरू होगी और 18406 **पटना - पुरी एक्सप्रेस** की सेवा **दिनांक** 24.05.2026 **(रविवार)** से शुरू होगी। ये ट्रेनें निम्नलिखित संक्षिप्त समयसूची, आवागमन के दिन, ठहराव और गठन के अनुसार चलेंगी:-

18405 पुरी - पटना एक्सप्रेस			स्टेशन	18406 पटना - पुरी एक्सप्रेस		
दिन	आ.	प्र.		आ.	प्र.	दिन
शनि	--	**14.55**	↓ पुरी	**09.45**	--	सोम
	21.15	21.25	खड़गपुर	01.10	01.20	
रवि	00.01	00.06	डानकुनी	22.25	22.30	रवि
	02.08	02.10	दुर्गापुर	20.13	20.15	
	03.18	03.20	चित्तरंजन	19.16	19.18	
	04.50	04.52	जसीडीह	17.45	17.47	
	11.15	--	पटना ↑	--	**13.20**	

उपर्युक्त ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग में खोरधा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर केन्दुझर रोड, भद्रक, बालेश्वर, आंदुल, बर्द्धमान, आसनसोल, मधुपुर, झाझा, किऊल, मोकामा, बाढ़ और बख्तियारपुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी। ● **चलने के दिन: पुरी से:** 18405 **दिनांक** 23.05.2026 से हर **शनिवार** को और **पटना से:** 18406 **दिनांक** 24.05.2026 से हर **रविवार** को। ● **गठन:** एसी 2-टियर: 01, एसी 3-टियर: 03, शयनयान श्रेणी: 08, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस): 04, जीएसएलआरडी: 02 = 18 कोच। ● **कैटेगरी:** एक्सप्रेस।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

छह जोड़ी ईएमयू ट्रेनों का निरस्तीकरण

बर्द्धमान स्टेशन क्षेत्र में ओल्ड कोचिंग लाइन पर डायमंड पॉइंट क्रॉसिंग नं. 366/365बी के नवीनीकरण के लिए, **दिनांक 17.05.2026 (रविवार) को 6 घंटे (10.00 बजे से 16.00 बजे तक) के लिए ट्रैफिक ब्लॉक** आवश्यक होगा। फलस्वरूप, निम्नलिखित ट्रेनें **दिनांक 17.05.2026 (रविवार)** को **निरस्त** रहेंगी: **बर्द्धमान से:** 36836, 36838, 36840, 37840, 36842, 31152, **हावड़ा से:** 37821, 37823, 36823, 36825, 37827, **सियालदह से:** 31151

विशेष टिप्पणी: ब्लॉक अवधि के दौरान स्पेशल या विलंब से चलने वाली ट्रेनें और कोई भी नई शुरू की गई ट्रेन/पार्सल ट्रेन/टीओडी, यदि कोई हो, मार्ग में सुविधानुसार नियंत्रित की जाएंगी/परिवर्तित मार्ग पर चलाई जाएंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्टेशनों की जनसंबोधन प्रणाली का पालन करें। असुविधा के लिए खेद है।

मंडल रेल प्रबंधक , हावड़ा

पूर्व रेलवे

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

आसनसोल मंडल के तहत नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों की नियंत्रण व्यवस्था

संयोजन

आसनसोल मंडल के तहत सीतारामपुर-झाझा अनुभाग के मधुरापुर स्टेशन में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों की नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में पूर्व प्रकाशित ऊपर शीर्षांकित विज्ञापन के संदर्भ में, यह उल्लेख किया जाता है कि नीचे उल्लेखित ट्रेनें भी निम्नानुसार नियंत्रित की जाएंगी:

अतिरिक्त ट्रेनों का पुनर्निर्धारण

● **17321 वास्को-द-गामा-जसीडीह साप्ताहिक एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 15.05.2026) 06 घंटे के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी (वास्को-द-गामा के स्थान पर धारवाड से यात्रा शुरू करेगी) तथा ● **08439 पुरी-पटना स्पेशल** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 16.05.2026), **08867 गोंदिया-रक्सौल साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 16.05.2026) तथा **04051 हावड़ा-नई दिल्ली ग्रीष्मकालीन स्पेशल** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 17.05.2026) 07 घंटे के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। असुविधा के लिए खेद है।

मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल

पूर्व रेलवे

हमें अनुसरण करें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी सूचना

एडमिन यूनिट/जोन: सियालदह मंडल-वाणिज्यिक, डीआरएम बिल्डिंग, काइजर स्ट्रीट, सियालदह, कोलकाता-700 014, **ऑक्शन कैटलॉग सं.:** पार्सल-एसडीएएच-60, **नीलामी करने वाले अधिकारी:** वरिष्ठ डीसीएम/सियालदह। **बोली प्रणाली:** सामान्य नीलामी (एकल चरण)। **नीलामी शुरू (सभी लॉट):** 29.05.2026 को 12.00 बजे। **नीलामी की अंतिम तिथि/समय:** 29.05.2026 को 14.10 बजे। **ऑटो एक्सटेंशन जोन:** 120 सेकंड। **ऑटो एक्सटेंशन अवधि:** 120 सेकंड। **प्रारंभिक कूलिंग ऑफ अवधि:** 30 मिनट। **लगातार लॉट का समापन अंतराल :** 10 मिनट। **अधिकतम ऑटो एक्सटेंशन:** 10 बार। **निर्णय का माध्यम:** ऑटो, **आरपी की प्रदर्शनी की गई**-नहीं। **आरपी से कम परमिट बिड** -हाँ। **क्या राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल (आरओएफआर) लागू है?:** नहीं। **विवरण:** एसएलआर कोच में पार्सल जगह (सिंगल कम्पार्टमेंट)(क्रम सं. एए/1 से एए/10 हेतु) और पार्सल वैन में पार्सल जगह (क्रम सं. एबी/1 हेतु)। **कैटेगरी:** (पार्सल-एसएलआर) (क्रम सं. एए/1 से एए/10 हेतु) और पार्सल-पार्सल वैन (क्रम सं. एबी/1 हेतु)। **क्रम सं., लॉट सं., ट्रिप/दिन, अंतिम तिथि/समय** निम्नानुसार हैं: **एए/1**, 12343-एसएलआर-एफ1-एसडीएएच-एचडीबी-26-3, 1096, 29.05.2026 को 12.30 बजे, **एए/2**, 12329-एसएलआर-एफ1-एसडीएएच-एएनवीटी-26-2 , 157, 29.05.2026 को 12.40 बजे, **एए/3**, 13137-एसएलआर-एफ1-केओएए-एनएमएच-26-2, 157, 29.05.2026 को 12.50 बजे, **एए/4**, 13105-एसएलआर-एफ1-एसडीएएच-बीयूआई-26-2, 627, 29.05.2026 को 13.00 बजे, **एए/5**, 13105-एसएलआर-एफ2-एसडीएएच-बीयूआई-26-1, 1096, 29.05.2026 को 13.10 बजे, **एए/6**, 13145-एसएलआर-एफ1-केओएए-आरडीपी-26-2, 470, 29.05.2026 को 13.20 बजे, **एए/7**, 12363-एसएलआर-एफ1-केओएए-एचडीबी-26-1, 470, 29.05.2026 को 13.30 बजे, **एए/8**, 12317-एसएलआर-एफ1-केओएए-एएसआर-26-1 , 313, 29.05.2026 को 13.40 बजे, **एए/9**, 13163-एसएलआर-एफ2-एसडीएएच-एसएचसी-26-1, 782, 29.05.2026 को 13.50 बजे, **एए/10**, 13121-एसएलआर-एफ1-केओएए-जीसीटी-26-1, 156, 29.05.2026 को 14.00 बजे, **एबी/1**, 13151-13152-वीपी-1-केओएए-जेएटी-26-3, 939, 29.05.2026 को 14.10 बजे।

रेट यूनिट: प्रति ट्रिप लाइसेंसिंग शुल्क (क्रम सं. एए/1 से एए/10 हेतु) और प्रति राउंड ट्रिप (दो तरफा) (क्रम सं. एबी/1 हेतु)। **न्यूनतम वृद्धि (%):** 0.2 (प्रत्येक हेतु)। **ईएमडी:** 10 ट्रिप का बोली मूल्य (न्यूनतम 5 लाख) (क्रम सं. एए/1 से एए/10 हेतु) और 5 राउंड ट्रिप का बोली मूल्य (न्यूनतम 10 लाख) (क्रम सं. एबी/1 हेतु) । **न्यूनतम टर्नओवर की आवश्यकता:** रु.0 (प्रत्येक हेतु)। **लॉट की स्थिति:** आरपी पेंडिंग (प्रत्येक हेतु)।

SDAH-42/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

दक्षिण पूर्व रेलवे - ई-निविदा

निविदा सूचना सं.: पीसीएमएम/जीईएनएल/टीपी/2026/18 **दिनांक: 15.05.2026**

"ई" प्रोक्योरमेंट प्रणाली के लिए निविदा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, मुख्यालय कार्यालय (5वीं मंजिल), नया प्रशासनिक भवन, 11, गार्डेन रीच रोड, कोलकाता-700043 के द्वारा खुली ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जो वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर निम्नानुसार अपलोड कर दी गई हैं। सभी निविदाएँ 14.00 बजे बंद की जाएंगी।

क्रम सं.	निविदा सं.	अंतिम तिथि	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	बयाना राशि (रु. में)
1.	90263067	03.06.26	एमएस वायर (सामान्य इंजी. उद्देश्य के लिए) 1.6 मिमी व्यास, 16 एसडब्ल्यूजी-सॉफ्ट आदि	81815 केजी	1,25,380/-
2.	60260018	22.06.26	फिश बोल्ट एवं नट 25 मिमी व्यास X 162 मिमी लंबा आदि	160000 अदद	2,40,520/-
3.	5626आरजीसी_मेन_एलईडी	17.06.26	मेन कलर एलईडी (लाल, हरा और पीला) आदि की आपूर्ति के लिए चालू ठेका/मूल्य अनुबंध	लाल= 2800 अदद हरा= 2500 अदद पीला= 4000 अदद	17,16,000/-
4.	38261527	12.06.26	कैसनब 22 एचएस बोगी (डिजाइन ए) के लिए 3 आइटमों से संलग्न पीयू पैड का किट	24974 सेट	20,00,000/-
5.	37260001ए	15.06.26	फैब्रिकेटेड साइड स्टैंचियन आदि	6906 अदद	3,07,480/-
6.	38263364ए	17.06.26	कैसनब 22 एचएस (मॉड 1) बोगी के लिए इनर बोलस्टर सस्पेंशन स्प्रिंग	5379 अदद	1,30,150/-
7.	38261512	22.06.26	कैसनब 22 एचएस बोगी के लिए मॉडिफाइड सेंटर पिवॉट टॉप (फ्लैट टाइप)	2266 अदद	3,41,190/-
8.	38261523	29.06.26	कैसनब 22 एनएलबी एवं कैसनब 22 एचएस बोगियों के लिए बोगी सेंटर पिवॉट टॉप (स्फेरिकल टाइप)	3745 अदद	3,40,270/-
9.	जीएसडी-केजीपी-अनलोडलोड 26-28ए	10.06.26	02 वर्षों के लिए रेलवे सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग एवं स्टैकिंग आदि	24000 एमटी	1,14,100/-
10.	33263366	13.07.26	व्हील सेट आदि के लिए कार्बन ब्रश असेंबली	16920 अदद	2,92,830/-
11.	33263065ए	06.07.26	फिएट आदि के लिए प्राइमरी वर्टिकल डैंपर	15420 अदद	12,74,190/-
12.	33263212	29.06.26	फिएट बोगी आदि का बोगी बोलस्टर	100 अदद	2,28,810/-
13.	33260004	22.05.26	एलडब्ल्यूएसीसीएन कोचों आदि के लिए सीट एवं बर्थ हेतु कुशनिंग मटेरियल	140 सेट	2,87,450/-
14.	31263446बी	22.06.26	वैक्यूम सर्किट ब्रेकर सिंगल बॉटल वीसीबी आदि	15 अदद	1,11,960/-
15.	30263503	04.08.26	नॉन-एस्बेस्टस आधारित 'के' टाइप हाई फ्रिक्शन कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक आदि	63400 अदद	3,54,550/-
16.	30261394	27.07.26	यूआईसी टाइप के लिए लैटरल साइड फ्लैंज (आरएच) आदि	560 अदद	2,56,920/-
17.	30263606	22.06.26	अपर फ्लैंज रबर वेस्टीब्यूल आदि	640 अदद	1,34,430/-
18.	30263530ए	15.06.26	203.2 मिमी X 95.25 मिमी ब्रेक सिलेंडर आदि	610 अदद	1,22,300/-
19.	40265043	09.06.26	3 X400 वर्ग मिमी, 19/33 केवी ग्रेड (अर्थेड सिस्टम), एचटी, थ्री कोर पावर केबल आदि	4700 एमटीआर	3,32,260/-
20.	29261376	08.06.26	कम्प्रेसर उपयुक्त आदि	149 अदद	1,28,450/-
21.	29263281	09.06.26	लॉक नट एफ.एस. ऑल-स्टील का सेट	576 सेट	13,32,180/-
22.	29263672	11.06.26	डब्ल्यूएजी-9 लोको के लिए वर्टिकल डैंपर आदि	395 अदद	1,24,710/-
23.	29264983	11.06.26	प्राइमरी करंट सेंसर	382 अदद	1,33,430/-
24.	29263252	15.06.26	होल्डर असेंबली के साथ अर्थ रिटर्न ब्रश	219 अदद	1,31,280/-
25.	29263318	16.06.26	डब्ल्यूएजी-9 लोको के लिए मूविंग कॉइल मीटर का सेट	214 सेट	1,67,210/-
26.	29263298	16.06.26	कार्बन स्लाइडिंग स्ट्रिप (एसके 85 सीयू)	344 अदद	1,66,430/-
27.	29263177	17.06.26	ट्रैक्शन मोटर आदि के लिए होल्डर	285 अदद	1,56,960/-
28.	29260010	18.06.26	थ्री फेज लोको के लिए 1 इंच एंड कॉक का सेट	344 सेट	1,33,450/-
29.	29263698	19.06.26	डब्ल्यूएपी-7 के लिए डैंपर का सेट	84 सेट	6,17,030/-
30.	29264674	26.06.26	ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर आदि के लिए मोटर	88 अदद	2,37,500/-
31.	25263405	08.07.26	इलास्टिक रिंग	1686 अदद	13,24,800/-
32.	29264755	09.07.26	लॉन्ग लाइफ। लोको साइड बफर आदि	412 अदद	4,37,550/-

इच्छुक निविदाकार निविदाओं के संपूर्ण विवरण/वर्णन/विनिर्देश के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देख सकते हैं एवं अपनी बोली ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में इन मदों के लिए मैनुअल निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। **द्रष्टव्य:** प्रत्याशित बोलीदाता सभी अन्य निविदाओं और तत्पश्चात प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र में भाग लेने के लिए, **www.ireps.gov.in** नियमित रूप से देख सकते हैं।

(PR-178)

कोलकाता की अधिकांश मस्जिदों के परिसर के भीतर ही अदा की गई नमाज

कोलकाता, समाज्ञा

कोलकाता में शुक्रवार को शहर की कई मस्जिदों में नमाज को लेकर नई व्यवस्था के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला। पुलिस की ओर से मिले निर्देशों और नए प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप नमाजियों ने सड़कों के बजाय मस्जिद परिसरों के भीतर ही नमाज अदा की। शहर के नाखोदा मस्जिद सहित रायड स्ट्रीट, बेनियापुकुर, खिदिरपुर, मोमिनपुर, तपसिया और पार्क सर्कस इलाके की कई मस्जिदों में अधिकांश लोगों ने मस्जिद परिसर के भीतर ही नमाज अदा की। भीड़ अधिक होने के कारण कुछ स्थानों पर लोगों को जगह नहीं मिली, जिसके चलते सीमित संख्या में लोगों को पास के फुटपाथ पर अस्थायी रूप से नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। नाखोदा मस्जिद में पुलिस ने सुबह से ही घोषणा कर दी थी कि नमाज परिसर के भीतर ही होगी। बाद में, मस्जिद ट्रस्टियों ने भीड़ को देखते हुए आगे से दो शिफ्ट में नमाज कराने पर विचार करने की बात कही है।

राजाबाजार में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर फैला भारी तनाव, पुलिस एक्शन के बाद भड़का गुस्सा, इलाके में जमकर कटा बवाल

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार नमाज को लेकर टकराव सामने आया है। शुक्रवार को सड़क पर नमाज पढ़ने के लेकर विवाद हो गया। इसके बाद, हंगामा हुआ और फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जानकारी के अनुसार, नामाजियों ने दावा कि वे सालों से सड़क पर नमाज पढ़ने आ रहे हैं। हालांकि, पुलिस के कड़े रुख के बाद नामाजियों ने सड़क खाली कर दी। यह घटना कोलकाता के राजाबाजार में हुई। कोलकाता में यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साफ कर चुके हैं कि सड़क पर नामाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। शुक्रवार को जब राजाबाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब लोग जमा हुए थे तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोक तो उन्होंने इसका विरोध किया। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की।

उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में दाखिले के लिए नोटिस किया जारी, आवेदन 18 मई से शुरू होगा

कोलकाता, समाज्ञा : उच्च माध्यमिक परीक्षा के नतीजे जारी होते ही उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में दाखिल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी कॉमन ऑनलाइन पोर्टल या सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया 18 मई से शुरू होगा और आगामी एक जून तक आवेदन दिए जा सकेंगे। गुरुवार को राज्य के अंडरग्रेजुएट लेवल के कॉलेजों में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस 18 मई से 1 जून तक चलेगा। कॉलेज बेस्ड मेरिट लिस्ट 9 जून को जारी की जाएगी। एडमिशन प्रोसेस का पहला फेज 9 से 15 साल के स्टूडेंट्स के लिए होगा। सीट अपग्रेडेशन 20 जून को होगा। अपग्रेडेड सीटों के लिए एडमिशन प्रोसेस 20 से 23 जून तक चलेगा। कॉलेजों में एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस 27 जून से 4 जुलाई तक चलेगा। नया सेशन 6 जुलाई से शुरू होगा। एडमिशन प्रोसेस का दूसरा फेज 7 जुलाई से शुरू होगा और सभी प्रोसेस 5 अगस्त तक चलेंगे। अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल खोला गया है। जिसके जरिए सोमवार की शाम 18 मई से राज्य के 460 डिग्री कॉलेजों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन जमा किए जा सकेंगे। अंडरग्रेजुएट एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने में 'बेस्ट ऑफ फोर' मेथड को अहमियत दी गई है।

ज्योतिप्रिय की बेटी को उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के सचिव पद से हटाया गया

कोलकाता, समाज्ञा : सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार ने कई प्रशासनिक बदलाव किए हैं। इस बार, ज्योतिप्रिय मल्लिक की बेटी प्रियदर्शिनी को उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के सचिव पद से हटा दिया गया है। इस बारे में, स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया। सुनने में आया है कि हाल ही में उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी गई थी। लेकिन, वह इसके लिए तैयार नहीं हुईं। इसके बाद, शिक्षा विभाग ने उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के सचिव पद से हटाने का फैसला किया। राज्य की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रियदर्शिनी मल्लिक को उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के सचिव पद से हटाया जा रहा है। इस बार, वह आशुतोष कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करेंगी।

कोलकाता में घरों के रजिस्ट्रेशन घटे, बड़े फ्लैटों की मांग बढ़ी

कोलकाता : कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया (केएमए) में अप्रैल 2026 के दौरान 4,796 आवासीय संपत्ति रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत कम रहे। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 की तुलना में भी रजिस्ट्रेशन में 5 प्रतिशत की गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि 501 से 1,000 वर्ग फुट वाले फ्लैट कुल लेन-देन का 59 प्रतिशत रहे, जबकि 500 वर्ग फुट से छोटे फ्लैटों की हिस्सेदारी घटकर 30 प्रतिशत रह गई। वहीं 1,000 वर्ग फुट से बड़े फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 179 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में कमी के बावजूद बाजार की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है।

आरजी कर मामला : पीड़िता के परिवार ने न्याय की जतायी उम्मीद

कोलकाता, समाज्ञा : आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकार हुई महिला चिकित्सक के अभिभावकों ने सरकार द्वारा जांच का दायरा बढ़ाने और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने के फैसले की शुक्रवार को सराहना की। पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि इस कदम से न्याय की उनकी उम्मीदें फिर से जगी हैं। उन्होंने कहा कि मामले में और अधिक गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पीड़िता की मां और भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि हाल के घटनाक्रम एक नयी न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत के संकेत हैं। देबनाथ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा जारी आदेश के लिए उन्हें धन्वाद देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि यह न्याय की राह में एक नए चरण की शुरुआत है। अब और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार भी ऐसे निर्देश जारी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किए। यही दोनों मुख्यमंत्रियों में अंतर है। पीड़िता की मां ने कहा कि परिवार ने जांच में बार-बार अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी बेटी के मामले में गलत जानकारी दी गई थी। हम मुख्यमंत्री के फैसले से खुश हैं। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि दोषियों को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने बार-बार कहा था कि दोषियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक मिसाल कायम की है ताकि कानून की रक्षा करने का जिम्मा संभालने वाले लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की हिम्मत न करें।

केंद्र और बंगाल ने पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

नयी दिल्ली/कोलकाता : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राज्य में पीएम श्री स्कूल योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पूर्व में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य ने शिक्षा के मामले में राज्य की स्वायत्तता का हवाला देते हुए इस योजना में शामिल होने का विरोध किया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के साथ धनराशि आवंटन को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नयी सरकार ने इस पहल को लागू करने का निर्णय लिया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार,

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव धीरज साहू और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव बिनोद कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर राज्य परियोजना निदेशक विभु गोयल, संयुक्त सचिव अमरप्रीत दुग्गल और निदेशक यूपी सिंह भी उपस्थित रहे।

हावड़ा मंडल में विकास कार्य के कारण कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

कोलकाता, समाज्ञा

पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में विकास एवं रखरखाव कार्यों के चलते आज यानी 16 मई को कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। समुद्रगढ़ और नवद्वीप धाम स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज संख्या 92 के रखरखाव कार्य तथा जिराट और गुप्तीपाड़ा स्टेशनों के बीच लिमिटेड हाइट सबवे निर्माण कार्य के कारण सुबह 8:20 बजे से शाम 4:10 बजे तक ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कई ईएमयू लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है। हावड़ा-कटवा मार्ग की ट्रेन संख्या 37913, 37915, 37917 और 37919 रद्द रहेंगी। बंडेल-कटवा मार्ग की 37747, 37749 और 37751 तथा सियालदह-कटवा की 31111 रद्द रहेगी। वहीं, कटवा-हावड़ा की 37918, 37920, 37922 और 37924, कटवा-बंडेल की 37744, 37746 और 37748 तथा कटवा-सियालदह की 31112 भी रद्द की गई हैं। इसके अलावा, 16 मई को चलने वाली 13465 हावड़ा-मालदह टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस अब अपने निर्धारित समय दोपहर 2 बजे के बजाय रात 8 बजे हावड़ा से रवाना होगी। वहीं, 13466 मालदह टाउन-हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस मालदह टाउन से सुबह 6:05 बजे के बजाय दोपहर 12:05 बजे प्रस्थान करेगी। ब्लॉक से पहले 13177 और 37916 अंतिम ट्रेनें होंगी, जबकि ब्लॉक समाप्त होने के बाद 13465 और 37926 पहली ट्रेनें होंगी।

मदर्स डे पर कोलकाता में चॉकलेट्स और होम डेकोर गिफ्ट्स की रही सबसे ज्यादा मांग

कोलकाता, समाज्ञा

मदर्स डे के अवसर पर कोलकाता में चॉकलेट्स सबसे पसंदीदा गिफ्ट के रूप में उभरे, जबकि कैंडल्स, डिफ्यूजर्स और होम डेकोर उत्पादों की मांग में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंस्टामार्ट की मदर्स डे गिफ्टिंग ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार, शहर में लोग अब पारंपरिक गिफ्ट्स से आगे बढ़कर अधिक सोच-समझकर और भावनात्मक जुड़ाव वाले उपहारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चॉकलेट्स और फूल देशभर में सबसे लोकप्रिय गिफ्ट्स रहे। वहीं, आइसक्रीम केक्स की बिक्री में 69 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी मांग शाम 7 बजे सबसे अधिक रही। ब्यूटी गिफ्ट पैक्स में 77 प्रतिशत और मसाजर्स की बिक्री में 136 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। कोलकाता और जयपुर में होम-ऐम्बियंस गिफ्टिंग का ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिला, जहां कैंडल्स, डिफ्यूज़र्स और डेकोर प्रोडक्ट्स की बिक्री में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि रात 8 से 9 बजे का समय सबसे व्यस्त गिफ्टिंग स्लॉट रहा, जबकि आखिरी समय में खरीदे गए टॉप 20 गिफ्ट आइटम्स में 15 चॉकलेट्स शामिल थीं।

नगरपालिका भर्ती घोटाला : ईडी का दावा, पूर्व मंत्री सुजीत बोस ने रिश्वत में लिए लग्जरी फ्लैट

कोलकाता, समाज्ञा : ईडी ने दावा किया है कि राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बोस ने नगरपालिकाओं में नौकरी दिलाने के बदले लिए लोगों से बतौर रिश्वत लग्जरी फ्लैट लिए थे। वह नगरपालिका भर्ती घोटाले के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल रहे हैं। बता दें कि गत 11 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह भी दावा किया है कि अवैध तरीके से जुटाई गई करोड़ों रुपये की नकदी को व्यवसायिक लेनदेन के जरिए वैध दिखाने के लिए लांड्रिंग की गई। यह मामला पहले सीबीआई की प्राथमिकी और कलकत्ता हाई कोर्ट के

निर्देशों के बाद सामने आया था। जांच में ओएमआर शीट में बड़े पैमाने पर हेरफेर के संकेत मिले हैं। ईडी का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई ठेके एक ही कंपनी को दिए गए थे, जिसकी पहचान एबीएस इंफोजोन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई है, जिसका संचालन अयान शील करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि ओएमआर शीट और मेरिट सूची में हेरफेर कर अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे और अन्य लाभ लेकर नियुक्त किया गया। तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसी ने लगभग 3.45 करोड़ रुपये नकद, कई संपत्ति दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। फिलहाल, सुजीत बोस अदालत के आदेश के तहत 10 दिन की ईडी हिरासत में हैं। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में अन्य राजनीतिक हस्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

कोलकाता डर्बी से पहले एक मंच पर आए ईस्ट बंगाल और मोहन बागान

कोलकाता, समाज्ञा

किंगफिशर स्ट्रॉन्ग पावर सोडा ने भारतीय फुटबॉल में एक खास पहल करते हुए कोलकाता डर्बी से पहले कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और मोहन बागान सुपर जायंट को एक मंच पर लाकर अपनी साझेदारी का जश्न मनाया। यह आयोजन हेनेकेन समूह की कंपनी यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (यूबीएल) द्वारा किया गया। इस अवसर पर यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड के मुख्य विपणन अधिकारी विक्रम बहल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक मजबूत सांस्कृतिक भावना है। उन्होंने कहा कि कोलकाता डर्बी का उत्साह, प्रतिद्वंद्विता और प्रशंसकों की दीवानगी देश में सबसे अलग और विशेष है। कार्यक्रम के दौरान एम्स्टेल ग्रांडे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ने भी मोहन बागान सुपर जायंट के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। कंपनी के अनुसार यह पहल भारतीय फुटबॉल और उसके तेजी से बढ़ते प्रशंसक वर्ग को समर्थन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल दर्शाती है कि यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड भारतीय फुटबॉल और उससे जुड़े जोशीले समुदायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लगातार मजबूत कर रही है।

बजाज समूह ने पूरे किए 100 वर्ष, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

मुंबई/कोलकाता : 148 बिलियन डॉलर मार्केट कैप वाले भारत के प्रमुख कारोबारी समूहों में शामिल बजाज समूह ने अपने 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह को शुभकामनाएं देते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। 1926 में जमनालाल बजाज द्वारा बॉम्बे (अब मुंबई) में स्थापित बजाज समूह आज 100 से अधिक कंपनियों के साथ 100 से ज्यादा देशों में कारोबार कर रहा है और 1.30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और मुकंद शामिल हैं। समूह जल्द ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी प्रवेश करने जा रहा है।

2037 तक शहरी बुनियादी ढांचे में 80 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत : ब्रिकवर्क रेटिंग्स

कोलकाता : ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट फ्रॉम ग्रांट्स टू मार्केट्स: हाउ अर्बन चैलेंज फंड विल रिशेप फाइनेंस इन इंडिया में कहा गया है कि तेज़ शहरीकरण और आर्थिक विकास को देखते हुए भारत को 2037 तक शहरी बुनियादी ढांचे में लगभग 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के अनुसार, 2036 तक देश की जीडीपी में शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे शहरों के लिए मजबूत और टिकाऊ वित्तीय व्यवस्था बनाना जरूरी हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र सरकार की 1 लाख करोड़ रुपये की अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) योजना शहरी विकास वित्त व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है और अगले पांच वर्षों में करीब 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश को सक्षम बना सकती है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मनु सहगल ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी योजना छोटे शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऋण जुटाना आसान बनाएगी।

हावड़ा की श्रेया सिंह ने रायगंज सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस (2020-2026) की पढ़ाई पूरी कर परिवार और शहर का नाम रोशन किया। दीक्षांत समारोह में वह अपने माता-पिता एवं परिवार के साथ मौजूद रहीं।

कोलकाता में ईपीएसआई और एपीएआई का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित

कोलकाता, समाज्ञा : एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया (ईपीएसआई) और एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस (एपीएआई), पश्चिम बंगाल के संयुक्त तत्वावधान में कोलकाता में स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, एक्रिडिटेशन एंड रैंकिंग परफॉर्मेंस विषय पर एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में शिक्षा एवं संस्थागत नेतृत्व क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इनमें सरदार तरणजीत सिंह, अध्यक्ष, एपीएआई एवं प्रबंध निदेशक, जेआईएस ग्रुप; पी. पलानीवेल, महासचिव, ईपीएसआई; डॉ. एच. चतुर्वेदी, संरक्षक, ईपीएसआई; डॉ. पुष्पति नाथ राजदान, प्रधान सलाहकार, क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्सीलेंस सेल, गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन (जीईएफ); प्रो. सी. आर. मुथुकृष्ण, पूर्व डीन (अकादमिक पाठ्यक्रम) एवं निदेशक-प्रभारी,

आईआईटी मद्रास; नवीन गोयल, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेरिटो; डॉ. वाई. एम. जयराज, प्रो-चांसलर, बीएलडीई; आशीष माहेश्वरी, निदेशक-शिक्षा, केपीएमजी; नारायणन रामास्वामी, पार्टनर एवं नेशनल लीडर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, केपीएमजी इंडिया; तथा डॉ. नीरज सक्सेना, प्रो-चांसलर, जेआईएस यूनिवर्सिटी शामिल रहे।

एफडीपी में एनबीए और एनआईआरएफ फ्रेमवर्क, आउटकम-बेस्ड एजुकेशन, रैंकिंग रणनीतियों और संस्थागत डेटा की पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान डाटा प्राइवेसी, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस इन हायर एजुकेशन विषय पर विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरदार तरणजीत सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम संस्थानों को बदलते शैक्षणिक मानकों और गुणवत्ता ढांचे के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

पूर्व रेलवे का 30 मिनट स्पार्कल अभियान, शिकायत के 30 मिनट के अंदर होगी सफाई

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे ने यात्रियों को स्वच्छ और बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्लीनिंग गारंटी विदिन 30 मिनट ऑफ रिपोर्टिंग अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह विशेष स्वच्छता अभियान 16 मई से 30 मई 2026 तक चलाया जाएगा। अभियान का औपचारिक शुभारंभ 16 मई यानी आज सियालदह रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर द्वारा किया जाएगा। वहीं, हावड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त महाप्रबंधक शीलेंद्र प्रताप सिंह समानांतर उद्घाटन कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। स्पॉट इट, रिपोर्ट इट, वी आर ऑन इट थीम पर आधारित इस अभियान के तहत यदि किसी यात्री को स्टेशन परिसर में गंदगी, कचरा या अस्वच्छता दिखाई देती है तो वह उसकी तस्वीर लेकर संबंधित मंडल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल - डीआरएमएसडीएएच, डीआरएमहावड़ा, डीआरएममालदह या डीआरएमआसनसोल को टैग करते हुए ईआरचैलेंज हैशटैग के साथ पोस्ट कर सकता है। शिकायत फेसबुक और रेलमदद के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायत सत्यापित होने के बाद विशेष रैपिड रिस्पॉन्स क्लीनिंग स्क्वॉड 30 मिनट के भीतर सफाई सुनिश्चित करेंगे। यह अभियान सियालदह, हावड़ा, मालदह और आसनसोल मंडल के सभी स्टेशनों पर लागू होगा। इसके तहत सियालदह, दमदम जंक्शन, बैरकपुर, नैहाटी, कांचरापाड़ा, बारासात, हावड़ा, लिलुआ, बंडेल जंक्शन, रामपुरहाट, आसनसोल, दुर्गापुर, मालदह, जमालपुर और भागलपुर सहित 15 प्रमुख स्टेशनों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने कहा कि रेलवे स्टेशन लाखों यात्रियों का दूसरा घर हैं और उनकी स्वच्छता बनाए रखना रेलवे और आम जनता दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

'एक छोटी सी लव स्टोरी' में दिखेगी अंकन- अद्रिजा की शानदार केमिस्ट्री

❑ 'सैयां' में अपनी अभिनय प्रतिभा से दिल जीतने वाले कोलकाता के अंकन अब नई भूमिका में

कोलकाता, समाज्ञा : मनोरंजन जगत के उभरते हुए कलाकार अंकन एक बार फिर अपने नए म्यूजिकल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। दिग्गज अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ चर्चित वीडियो 'सैयां' में अपनी अभिनय प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीतने वाले कोलकाता के अंकन अब किंगडम प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही नई म्यूजिकल फिल्म 'एक छोटी सी लव स्टोरी' में नजर आएंगे। इस म्यूजिकल वीडियो में अंकन के साथ मुख्य भूमिका में अद्रिजा दिखाई देंगी। निर्माताओं के अनुसार, दोनों कलाकारों की मासूमियत, सादगी और शानदार केमिस्ट्री इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है। वीडियो में दोनों की ऑन-स्क्रीन मौजूदगी दर्शकों को एक अलग ही रोमांटिक और भावनात्मक दुनिया में ले जाएगी।

युवा फिल्म कलाकार अंकन ने बताया कि 'एक छोटी सी लव स्टोरी' आज की जन-ज़ी पीढ़ी की भावनाओं और आधुनिक रिश्तों पर आधारित कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और डिजिटल दुनिया के जरिए दो किशोर धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आते हैं। कहानी को हल्के-फुल्के लेकिन भावनात्मक अंदाज में पेश किया गया है, जिससे युवा दर्शक खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस कर सकेंगे।

हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ सुंदरबन पुलिस का अभियान

कोलकाता : सड़क सुरक्षा को लेकर सुंदरबन पुलिस जिले की ओर से शुक्रवार को व्यापक अभियान चलाया गया। हेलमेट नहीं पहनने वाले बाइक चालकों को जागरूक करने के लिए पुलिस सड़क पर उतरी। मंदरबाजार के विजयगंज बाजार में सुंदरबन पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौस्तभदीप आचार्य ने स्वयं मौजूद रहकर बाइक चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस दौरान एसडीपीओ प्रसेंजित दास, मंदरबाजार थाना प्रभारी कौशिक नाग और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने चेतावनी दी कि आगे से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मंदरबाजार थाना परिसर में नागरिक सुरक्षा, विजयगंज बाजार में यातायात जाम और डीजे व तेज आवाज में माइक बजाने को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की गई थीं।

दादा की हत्या मामले में बेटे के खिलाफ पोते की गवाही, बनगांव अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

कोलकाता : बनगांव में दादा की हत्या के मामले में एक बेटे की अपने ही पिता के खिलाफ दी गई गवाही अदालत में अहम साबित हुई। इसी गवाही और मेडिकल सबूतों के आधार पर बनगांव महकमा अदालत ने आरोपी तपन विश्वास को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।

मामले की जानकारी देते हुए बनगांव महकमा अदालत के अधिवक्ता जॉयदेव हालदार ने बताया कि मेडिकल प्रमाणों और आरोपी तपन विश्वास के बेटे तन्मय विश्वास की गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अदालत सूत्रों के अनुसार, घटना 12 दिसंबर 2020 की है। मृतक चित्तरंजन विश्वास बनगांव थाना क्षेत्र के ढाका पाड़ा इलाके के निवासी थे। आरोप था कि उनका बड़ा बेटा तपन विश्वास पिता की पूरी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहता था। जब वृद्ध पिता ने इसका विरोध किया, तब धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई।

इस पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी आरोपी का बेटा और मृतक का पोता तन्मय विश्वास था। घटना के बाद बनगांव थाने में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तपन विश्वास को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में था और मामले की सुनवाई चल रही थी।

सूत्रों के मुताबिक, मामले में शुरुआत में कुल 14 लोगों ने गवाह बनने की बात कही थी। आरोपी की पत्नी ने भी शुरुआत में पति के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन बाद में वह और अन्य आठ गवाह अदालत में गवाही देने से पीछे हट गए। इसके बावजूद आरोपी का बेटा तन्मय अपने बयान से नहीं मुकरा और उसने अदालत में स्पष्ट कहा कि उसके पिता ने ही उसके दादा की हत्या की थी।

अदालत ने सभी सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट और मुख्य गवाह तन्मय विश्वास के बयान का विस्तृत परीक्षण करने के बाद आरोपी तपन विश्वास को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

तिलजला में फिलहाल नहीं चलेगा 'बुलडोजर एक्शन'

कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

कोलकाता : तिलजला इलाके में कथित अवैध निर्माण को लेकर चल रही कार्रवाई पर फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधुरी की अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि फिलहाल संबंधित बहुमंजिला इमारत को और नहीं तोड़ा जाएगा तथा मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यदि पहले से तोड़े गए हिस्से किसी तरह से खतरनाक स्थिति में हैं, तो नगर निगम भवन मालिक से बातचीत कर आवश्यक कदम उठा सकता है। अदालत ने पुलिस और नगर निगम को सभी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर करने का निर्देश

दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजा बसु चौधुरी ने अवैध निर्माण को लेकर चिंता जताते हुए कहा, मशरूम की तरह अवैध निर्माण हो रहे हैं। यह भविष्य में बड़ी आपदा को जन्म दे सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि भवन मालिक अब तक इमारत का स्वीकृत नक्शा पेश नहीं कर सके हैं। साथ ही जिस प्रकार के व्यवसाय का संचालन भवन में होने का दावा किया गया, उससे संबंधित कोई वैध दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी कारण अदालत ने फिलहाल इमारत में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगा दी।

सुनवाई के दौरान भवन मालिक ने दावा किया कि नगर निगम ने भवन तोड़ने की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की। उनका कहना था कि इमारत में कोई टैनरी नहीं चल रही थी। भवन मालिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत में कहा कि भवन तोड़ने के बाद उन्हें थाने बुलाकर जबरन यह लिखवाया गया कि पहले ही तोड़फोड़ का नोटिस दिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किस सरकारी विभाग ने कार्रवाई की, इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। भवन मालिक ने अदालत से अनुरोध किया कि इमारत को आगे न तोड़ा जाए और बिजली तथा पानी का कनेक्शन फिर से बहाल किया जाए।

वहीं राज्य सरकार की ओर से भवन मालिक के आरोपों को खारिज किया गया। सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि संबंधित परिसर में फैक्टरी संचालन के लिए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया था। भवन के पास फायर लाइसेंस नहीं था और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी नहीं ली गई थी। राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि नोटिस दिया गया था, लेकिन भवन मालिक ने उसे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद नोटिस भवन की दीवार पर चिपका दिया गया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने फिलहाल तिलजला में किसी भी प्रकार की नई 'बुलडोजर कार्रवाई' पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर, एसएसकेएम अस्पताल में की उच्च स्तरीय बैठक

- दलाल राज से लेकर रेफरल दूर करने का निर्देश, बनेगा वॉर रूम और सीएम खुद करेंगे निगरानी
- डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों तक सभी के लिए आईडी कार्ड जरूरी

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य के अस्पतालों की 'रेफर बीमारी' को ठीक करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने एसएसकेएम अस्पताल के हेल्थ डायरेक्टर और कोलकाता के अस्पतालों के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग में सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अस्पतालों में दलाली और रेफरल-बीमारी को रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, हेल्थ बिल्डिंग में एक वॉर रूम बनाया जाएगा। वह लिंक मुख्यमंत्री के कमरे में होगा। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा, डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों तक सभी के लिए आईडी कार्ड जरूरी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जल्द ही निजी अस्पतालों में 15 परसेंट बेड इस्तेमाल करने के लिए मीटिंग करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, मूल रूप से कोलकाता के लगभग सभी अस्पतालों के प्रिंसिपल, ज़िम्मेदार अधिकारियों और

एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दलाली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पतालों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। बेड की संख्या और कितने मरीज हैं, यह बताया जाना चाहिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी मजबूत करने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कैंपस परिसर में बाहरी लोगों के आने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पूरे राज्य में ऐप-बेस्ड एम्बुलेंस सिस्टम बनाया जाएगा। एम्बुलेंस में जीपीएस ट्रैकर होंगे।

राज्य सरकार ने 2011 के बाद जारी किए गए जाति प्रमाणपत्रों के पुनः सत्यापन का दिया आदेश

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों का पुन: सत्यापन करने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर पुन: सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। राज्य के जनजातीय विकास और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री क्षुदिराम टुडू ने कहा कि उस दौरान कई फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। टुडू ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में बड़ी संख्या में फर्जी एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए और कई लोगों ने इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल करके लाभ उठाया। मंत्री ने पहले कहा था कि जिन अधिकारियों की देखरेख में ऐसे प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व मंत्री रथिन बोस भर्ती घोटाला मामले में ईडी के समक्ष हुए पेश

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री रथिन घोष शुक्रवार को कथित नगर निकाय भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। बता दें कि इससे पहले वह पांच बार जारी समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस दिन, सुबह करीब 10 बजे रथिन घोष सॉल्टलेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे और कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें किस कारण से बुलाया गया है। कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों बुलाया गया है। अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। उल्लेखनीय है कि ईडी अधिकारियों द्वारा उनसे नगर निकायों में पैसे लेकर भर्ती किए जाने के आरोपों से जुड़ी जांच में पूछताछ किए जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे ने तीन परियोजनाओं को दी मंजूरी

कई लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू

कोलकाता, समाज्ञा : भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को राज्य के लिए तीन नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, उन्हें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से परियोजनाओं से संबंधित तीन अलग-अलग पत्र प्राप्त हुए थे। इन तीन परियोजनाओं में से पहली परियोजना राज्य के उत्तरी क्षेत्र में नई जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी रेलवे लाइन परियोजना की मंजूरी से संबंधित है। दूसरी परियोजना हावड़ा क्षेत्र के संतरागाछी को राजस्थान के जयपुर के खातिपुरा क्षेत्र से जोड़ने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन, संतरागाछी-खातिपुरा एक्सप्रेस (खड़गपुर होते हुए) के संचालन की मंजूरी से संबंधित है। तीसरा विषय पत्र पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी से पुरुलिया जिले के आद्रा जंक्शन तक 107 किलोमीटर लंबी तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की मंजूरी से संबंधित है। इसी बीच, रेल मंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर घोषणा की कि कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सॉल्टलेक के पास चिंगरीघाटा में लंबे समय से लंबित कोलकाता मेट्रो कनेक्शन का काम शुक्रवार की रात से शुरू हो रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान यह कनेक्शन का काम लंबे समय तक शुरू नहीं हो सका था क्योंकि कोलकाता पुलिस ने चिंगरीघाटा में यातायात प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दी थी, जो काम के निष्पादन के लिए आवश्यक था। रेल मंत्री ने शुक्रवार की दोपहर को जारी अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। डबल इंजन वाली सरकार सत्ता में आई है। तीन साल से अटकी चिंगरीघाटा की समस्या का समाधान हो गया है। कोलकाता पुलिस से भी अनुमति मिल गई है। अब काम शुरू हो रहा है।

भाजपा की शिकायत के बाद कैनिंग थाने का आईसी निलंबित

कोलकाता, समाज्ञा

दक्षिण 24 परगना जिला में चुनाव बाद हिंसा के कारण तनाव व्याप्त है। इस कड़ी में, गोसाबा से भाजपा विधायक विकर्ण नस्कर ने इलाके में तृणमूल के गुंडों की हिंसा के आरोपों को लेकर गुरुवार को कैनिंग थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अब, 24 घंटे से भी कम समय में, कैनिंग थाने के आईसी अमित हाति को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने गुरुवार की रात से कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि, कैनिंग थाने के जांचकर्ताओं ने दावा किया कि किसी भी बदमाश या किसी

भी हथियार का कोई निशान नहीं मिला। उसके बाद, जिला पुलिस सूत्रों ने बताया कि कैनिंग थाने के आईसी अमित हाति को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, निलंबित आईसी की जगह अभी तक किसी नए व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। बारुईपुर जिला मुख्यालय फिलहाल इस थाने का इंचार्ज होगा।

उत्तर कोलकाता के विभिन्न इलाकों में चला अतिक्रमण मुक्त अभियान

कोलकाता, समाज्ञा : हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर कोलकाता के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को अवैध हॉकरों द्वारा सड़कों पर किए गए अतिक्रमण पर डंडा चलाया गया। पता चला है कि हॉकर अवैध रूप से सड़कों पर दुकान लगाए हुए है और धंधा कर रहे है। इस दिन, हावड़ा ब्रिज ट्रैफिक गार्ड ओसी शौभिक बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता पुलिस ने कलाकार स्ट्रीट, एमजी रोड, ब्राबोर्न रोड समेत कई रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराया। बताया गया है कि इन सबके पास केएमसी द्वारा अनुमोदित कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं है और ये अवैध रूप से सड़कों पर धड़ल्ले से धंधा करते आ रहे है। पुलिस की इस

कार्रवाई से आस-पास एवं राहगीरों को काफी राहत मिलेगी।

कोलकाता पुलिस के डीसी शांतनु सिन्हा बिस्वास को 14 दिन की ईडी हिरासत

ईडी ने डीसी पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस-अपराधी गठजोड़ से अवैध धंधे चलाने का आरोप

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (डीसी) शांतनु सिन्हा को शुक्रवार को 14 दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया। इस बीच, ईडी ने अदालत में कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इनमें जमीन पर कब्जा, पुलिस अधिकारियों के तबादले में प्रभाव डालना, पत्नी और पुत्र के नाम पर व्यवसाय चलाना, कई मेडिकल कालेजों में कैंटीन संचालन, जांच में असहयोग और करोड़ों रुपये के लेनदेन शामिल हैं। अपराधी विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से साठगांठ के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किए गए शांतनु को शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी के अनुसार, बेहाला के व्यवसायी जय कामदार के साथ मिलकर शांतनु जमीन कारोबार में

अवैध हस्तक्षेप करते थे। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि जमीन कब्जा कराने में अपराधियों की मदद ली जाती थी। दक्षिण कोलकाता के कुख्यात सोना पप्पू की भूमिका जमीन मालिकों को धमकाने की थी। ईडी का दावा है कि पुलिस और अपराध जगत के गठजोड़ के जरिए यह पूरा नेटवर्क संचालित होता था। ईडी ने कहा कि जय कामदार के चैट, बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों से कई महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। वहीं, शांतनु ने दावा किया कि जय कामदार ने उन्हें कुछ उपहार दिए थे।

ईडी के अनुसार, शांतनु ने कांदी स्थित घर के आधुनिकीकरण पर करीब 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए। शांतनु की पत्नी के नाम पर पांच मेडिकल कालेजों में कैंटीन व्यवसाय चलाया जा रहा था, जिसमें कोलकाता पुलिस का ही एक अधिकारी साझेदार बताया गया है। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि बिल्डरों से वसूली का संगठित नेटवर्क चलाया जाता था। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसे देने पड़ते थे। स्थानीय काउंसिलरों और सिंडिकेट के जरिए निर्माण कार्य नियंत्रित किया जाता था। यहां तक कि बिना भुगतान कोई प्लंबर भी काम शुरू नहीं कर सकता था। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि जब्त दस्तावेजों से पूर्व सरकार के राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संपर्क के संकेत मिले हैं। फिलहाल ईडी पूरे नेटवर्क की वित्तीय और आपराधिक जांच में जुटी है।

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, झारखंड से लाई गई थी वारदात में इस्तेमाल की गई कार

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या में इस्तेमाल की गई चारपहिया गाड़ी झारखंड से लाई गई थी और पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद उसका नंबर प्लेट बदल दिया गया था। सूत्रों के अनुसार, मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों में से एक मयंक राज मिश्रा ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसे झारखंड के एक व्यक्ति ने उक्त वाहन को झारखंड से उत्तर 24 परगना जिले के बारासात तक पहुंचाने का जिम्मा दिया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, मयंक ने कबूल किया है कि वह झारखंड से वाहन चलाकर बारासात पहुंचा और

वहां एक सुनसान स्थान पर गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर नकली नंबर लगा दिया। बताया जा रहा है कि असली नंबर प्लेट दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहन का था। सूत्रों ने यह भी बताया कि मयंक को वाहन पहुंचाने के बदले एक लाख रुपये दिए गए थे। बारासात में वाहन सौंपने के बाद वह हावड़ा स्टेशन पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर बक्सर चला गया, जहां बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

बहरमपुर कोर्ट-लालगोला नई ईएमयू लोकल सेवा शुरू, यात्रियों को मिलेगा लाभ

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे ने सियालदह मंडल में नई 31777 बहरमपुर कोर्ट-लालगोला ईएमयू लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने तथा मौजूदा 31776 कृष्णपुर-कॉसिमबाजार लोकल ट्रेन को बहरमपुर कोर्ट तक विस्तार देने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 18 मई 2026 से लागू होगी। बहरमपुर कोर्ट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य पूरा होने तथा अतिरिक्त हाई-लेवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। नई समय-सारिणी के अनुसार 31776 कृष्णपुर-बहरमपुर लोकल ट्रेन प्रतिदिन सुबह 6:55 बजे कृष्णपुर स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी और सुबह 7:47 बजे बहरमपुर कोर्ट स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद नई 31777 बहरमपुर कोर्ट-लालगोला ईएमयू लोकल ट्रेन सुबह 8:35 बजे बहरमपुर कोर्ट स्टेशन से प्रस्थान कर सुबह 9:35 बजे लालगोला पहुंचेगी।

संदेशखाली में गायों से भरे वाहन को रेखा पात्र ने रोका

भाजपा विधायक ने प्रशासन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया

कोलकाता, समाज्ञा : संदेशखाली की चर्चित नेता और हिंगलगंज की भाजपा विधायक रेखा पात्र ने शुक्रवार को अवैध मवेशी आवागमन के खिलाफ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। हिंगलगंज के दुलदुली फेरीघाट इलाके से कथित तौर पर अवैध रूप से गायों को ले जाया जा रहा था, जिसे उन्होंने बीच रास्ते में ही रुकवा दिया। इसके बाद, सभी पशुओं को सडक़ किनारे एक पेड़ की छांव में बांध दिया गया और उनके लिए चारा तथा पानी की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पशु व्यापार और उम्र संबंधी नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए। उनके अनुसार, कम उम्र की गायों की खरीद-बिक्री पर रोक के बावजूद इस तरह की गतिविधियां जारी हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद अवैध पशु कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद गायों को आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षित रूप से छोडऩे की प्रक्रिया की गई।

हावड़ा के सब्जी बाजार में युवक की बेरहमी से हत्या, व्यापारियों में दहशत

हावड़ा : हावड़ा स्टेशन से सटे थोक सब्जी बाजार में गुरुवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राइस चौधरी उर्फ भोला (30) के रूप में हुई है, जो इलाके का कथित छिनताईबाज बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब साढ़े 11 बजे की है। युवक कुछ साथियों के साथ बाजार इलाके में शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उसके साथ मौजूद लोगों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक खून से लथपथ हालत में

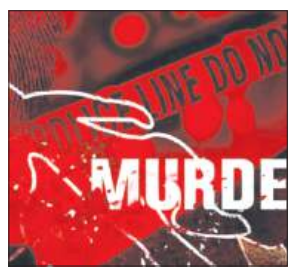

घटनास्थल पर तड़पता रहा। घटना की सूचना मिलते ही गोलाबाड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत हावड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान मिले हैं तथा उसका गला भी काटा गया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

घटना के बाद सब्जी बाजार के व्यापारियों में दहशत फैल गई है। हावड़ा स्टेशन एरिया होलसेल वेजिटेबल मार्केट एसोसिएशन के सचिव विनय सोनकर ने आरोप लगाया कि रात के समय बाजार में बाहरी लोग विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में पर्याप्त पुलिस निगरानी नहीं होने के कारण व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

हावड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, लिलुआ से दो कुख्यात आरोपी गिरफ्तार

हावड़ा : हावड़ा में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हावड़ा सिटी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तर हावड़ा के कुख्यात अपराधी आकाश सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब लिलुआ थाना पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान रंजीत कर्मकार उर्फ लालू और राजबीर सिंह उर्फ घेंटू के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों के खिलाफ जबरन जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूली और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लंबे समय से दर्ज थे। बताया जा रहा है कि दोनों इलाके में काफी सक्रिय थे और स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ था। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि दोनों आरोपित सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के करीबी माने जाते थे। चर्चा यह भी है कि एक आरोपित का संबंध कैलाश मिश्रा से तथा दूसरे का डोमजूर के वर्तमान विधायक तापस माइती के करीबी के तौर पर बताया जा रहा है।

हालांकि, पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विधानसभा चुनाव के बाद इलाके में कानून-व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए हावड़ा सिटी पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है।

इसी अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है।

'जिसे जाना है जाए, मैं नए सिरे से पार्टी का गठन करूंगी', दलबदल के कयास के बीच ममता ने दिया संदेश

कोलकाता, समाज्ञा

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक के दौरान स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, लेकिन संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जाएगा। शनिवार को कालीघाट स्थित अपने आवास पर हुई इस बैठक में ममता बनर्जी ने हारे हुए उम्मीदवारों से बातचीत की और संगठन को दोबारा खड़ा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता साथ बने रहना चाहते हैं, वे टूटे हुए पार्टी कार्यालयों को फिर से दुरुस्त करें

और उन्हें पुनः सक्रिय करें। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर वह स्वयं भी कार्यालयों के रंग-रोगन में हिस्सा लेंगी। ममता ने यह भी दोहराया कि तृणमूल कांग्रेस कभी भी हार नहीं मानेगी और जनता के फैसले को स्वीकार किया गया है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित एक पार्टी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व से अगले सात दिनों के भीतर क्षेत्र आधारित जनसंपर्क कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, उन्होंने पार्टी नेताओं को राज्य के बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में जहां भी संभव हो, ब्लॉक स्तर, नगर स्तर और क्षेत्र स्तर की बैठकें शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला नेताओं से चुनाव के बाद कथित तौर पर विस्थापित हुए लोगों की सूची सीधे दक्षिण कोलकाता स्थित उनके कालीघाट आवास-सह-कार्यालय में उन्हें सौंपने को भी कहा। ममता ने पूर्व वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो स्वयं एक वकील भी हैं, को चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण कथित तौर पर विस्थापित हुए लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा सौंपा। पार्टी नेता ने आगे कहा कि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस में संगठनात्मक मामलों में अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर पार्टी नेताओं को सार्वजनिक बयान देने या मीडिया से बात करने के बजाय पार्टी के भीतर ही अपनी बात रखनी चाहिए।

सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने के लिए शुभेंदु सरकार की त्रिपक्षीय रणनीति

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि सौंपने की त्रिपक्षीय रणनीति अपनाई है। राज्य सचिवालय में भूमि हस्तांतरण रणनीति से अवगत सूत्रों ने बताया कि योजना का पहला हिस्सा यह है कि बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित सरकारी भूमि तुरंत बीएसएफ को उपलब्ध कराई जाए, ताकि कांटेदार बाड़ लगाने का पहला चरण तुरंत शुरू हो सके। रणनीति का दूसरा हिस्सा यह है कि मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक उचित पारिश्रमिक का भुगतान करके सीमा के निकट

स्थित निजी भूमि को भूस्वामियों से अधिग्रहित किया जाए और बाद में उस भूमि को बीएसएफ को सौंप दिया जाए ताकि दूसरे चरण की शुरुआत की जा सके। भूमि हस्तांतरण में तीसरी रणनीति के तहत बिना बाड़ वाली सीमाओं के निकट अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करना और फिर उस भूमि को बीएसएफ को सौंपना शामिल होगा, जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। सूत्रों ने बताया कि भूमि हस्तांतरण रणनीति के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रणनीति के अनुसार प्रत्येक चरण के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। पूरी प्रक्रिया मंत्रिमंडल द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय की तारीख से 45 दिनों की अंतिम समय सीमा के भीतर निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। राज्य की पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को विकास कार्यों के लिए प्रधान समन्वयक के रूप में पूरी प्रक्रिया की देखरेख करने और बीएसएफ को भूमि का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

उप्र: ट्रक ने दो शिक्षकों को कुचला, मौत

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शुक्रवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में बेसिक शिक्षा विभाग के दो शिक्षकों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों शिक्षक मोटरसाइकिल से परीक्षा ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि तभी बरेली-शाहजहांपुर राजमार्ग पर फरीदपुर टोल प्लाजा के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, हादसा इतना भयावह था कि दोनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइंस निवासी पीके यादव और मुंशीनगर निवासी प्रमोद यादव फरीदपुर ब्लॉक के लोंगपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह दोनों रोज की तरह साथ में परीक्षा ड्यूटी के लिए निकले थे। फरीदपुर थाना प्रभारी राधे श्याम ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों सहित तीन लोगों की मौत

जयपुर : राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृतकों में चित्तौड़गढ़ स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाने का एक हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल शामिल हैं। उसने बताया कि यह हादसा जयपुर-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मांडल चौराहे के पास हुआ जब जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

'डबल इंजन' सरकार ने माफिया, अराजकता और दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर सुशासन का माहौल बनाया: योगी

महराजगंज : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि 'डबल इंजन' सरकार ने माफिया, अराजकता और दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर प्रदेश में सुशासन का माहौल बनाया है। योगी ने महराजगंज में 208 करोड़ रुपये से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सही वोट से विकास, सुरक्षा, रोजगार और सुशासन सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार ने माफिया, अराजकता और दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर प्रदेश में सुशासन का माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्वांचल को माफिया और भय के माहौल से बाहर निकालकर विकास, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, रोजगार और सुरक्षा से जोड़ा गया है।

प्लास्टिक, घरेलू कचरे को नालियों में न फेंकें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोगों से प्लास्टिक, कपड़े और घरेलू कचरे को नालियों में नहीं डालने की अपील करते हुए कहा कि शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं जलभराव व मौसमी बीमारियों से मुक्त रखने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 495 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने शहर में नागरिक समस्याओं, विशेष रूप से जलभराव, मच्छर से संबंधित मुद्दों और मानसून के मौसम के दौरान और उसके बाद उभरने वाली बीमारियों को हल करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है।

कुमार विश्वास, 'आप' नेताओं से जुड़े मुकदमे की सुनवाई टली

सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक सोमनाथ भारती से जुड़े एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। सांसद/विधायक अदालत में तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई पांच जून के लिए तय कर दी गयी। मामले की पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी और अदालत ने सभी के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 15 मई को पेश होने को कहा था। यह मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है और उस दौरान अमेठी थाने में इन नेताओं के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया था। अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने तीनों नेताओं को समन जारी कर तलब किया था लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि आरोपियों को समन की तामील हो चुकी है या नहीं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 'आप' ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को उम्मीदवार बनाया था।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। आशुतोष महाराज ने प्रयागराज में पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया था। अवमानना याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने कहा कि यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो याचिकाकर्ता के पास इस अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन दाखिल करने का वैधानिक उपाय उपलब्ध है। इससे पहले न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस अवमानना याचिका पर सुनवाई से स्वयं को यह कहते हुए अलग कर लिया था कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामला न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत को सौंप दिया था।

गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान में असीम संभावनाएं: मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता, प्रभावी और स्थायी विकल्प है तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण व संयमित उपभोग की आदत ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह को प्रशस्त करेगी। शर्मा, यहां 'राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाओं के साथ राजस्थान हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना पर आधारित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईंधन की एक-एक बूंद बचाने के मंत्र को अपनाते हुए राज्य सरकार ने राजकीय वाहनों के सीमित और संयमित उपयोग व ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से पहुंचे और ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन की बचत जनभागीदारी से जुड़ा व्यापक जनआंदोलन है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प लिया है कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है।

बिहार: प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल पहुंचे कार्यालय

पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने को लेकर की गयी अपील के कुछ दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने सरकारी आवास से मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यालय तक पैदल पहुंचे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी लोक सेवक आवास (मुख्यमंत्री आवास) से मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यालय तक पैदल गए। प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने की अपील के बाद बिहार सरकार ने हाल में कई कदम उठाए हैं। इनमें सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाना और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए वाहनों के नियमित उपयोग में कटौती शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या भी कम कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पश्चिम एशिया संकट की तुलना वैश्विक कोविड महामारी से करते हुए ईंधन बचत की अपील किए जाने के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वह अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर रहे हैं और मंत्रियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से भी ऐसा करने की अपेक्षा करते हैं।

झारखंड भाजपा की बैठक में एसआईआर और किसानों के मुद्दों पर चर्चा

रांची : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई के पदाधिकारियों की शुक्रवार को हुई बैठक में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और तूफान तथा बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा हुई। एक भाजपा नेता ने यह जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने की और इसमें झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी तथा अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा के राज्य महासचिव गणेश मिश्रा ने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा, हमें पता है कि झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हमने इस बारे में विस्तार से चर्चा की। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि वे अपने-अपने बूथ स्तर के एजेंट के नाम और फोटो सत्यापित करके जिला चुनाव कार्यालय में जमा करें। भाजपा ने यह काम पहले ही पूरा कर लिया है।

एक मां ने पांच दिन में चार बच्चों को दिया जन्म, सभी स्वस्थ

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक महिला ने मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर अस्पताल में पांच दिन के अंतराल में चार बच्चों को सामान्य प्रसव से जन्म दिया। चिकित्सकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चिकित्सकों ने इसे दुर्लभ मामला बताया। अस्पताल के अनुसार, संभल के ओवरी गांव की रहने वाली अमीना ने नौ मई को पहले बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद 14 मई को चिकित्सकों की निगरानी में तीन अन्य बच्चों का जन्म हुआ। अस्पताल ने बताया कि चार नवजात बच्चों में दो बेटे और दो बेटियां हैं और अमीना छह मई को इस अस्पताल में भर्ती हुई थीं। डॉ. शुभ्रा अग्रवाल के नेतृत्व वाली टीम ने जटिलता के बावजूद सफलता प्राप्त की। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह अस्पताल में पहला मामला है, जहां चार बच्चों का सामान्य प्रसव हुआ। उन्होंने बताया कि महिला का इलाज गर्भावस्था के तीसरे महीने से हो रहा था और अल्ट्रासाउंड में चार भ्रूणों की पुष्टि हुई थी। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जटिलता को देखते हुए पहले भ्रूण संख्या कम करने की सलाह दी गई थी लेकिन परिवार ने गर्भ जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल चारों शिशुओं को एहतियातन वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है तथा मां अमीना स्वस्थ हैं।

बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने की तैयारियां समय से पहले पूरी हों : विजय कुमार चौधरी

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी योजनाओं को निर्धारित समय से पहले और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ और अल्प वर्षा, दोनों परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और जानबूझकर कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग के मंत्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को अंतिम समय तक लंबित रखने के बजाय निर्धारित मानकों के अनुरूप समय से पहले पूरा किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्मूल्यांकन कर कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी प्रशंसा के पात्र होंगे, जबकि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में राज्य के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए कटाव निरोधी कार्यों की प्रगति, तटबंधों की मरम्मत एवं रखरखाव, बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्री की उपलब्धता तथा संवेदनशील स्थलों की निगरानी पर विस्तृत चर्चा की गई। कटाव निरोधी कार्यों की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कार्यों को एक माह में पूरा किया जा सकता है, उनके लिए दो माह का समय निर्धारित कर अनावश्यक विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला

पटना : बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 15 अधिकारियों का तबादला किया और कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अधिसूचना में बताया गया कि इसके साथ ही एच. आर. श्रीनिवास को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया। अधिसूचना के अनुसार, कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पंकज कुमार पाल को विभाग का पूर्णकालिक सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने कई प्रमंडलों में आयुक्तों के स्तर पर भी फेरबदल किया। अधिसूचना के अनुसार, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय को कोसी प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार को पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त अवनीश कुमार सिंह को खान एवं भू-तत्व विभाग में सचिव-सह-खान आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अगर मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करनी पड़े, तो वह जगह मेरे लिए नहीं है: कोहली

नयी दिल्ली : विराट कोहली को अब भी क्रिकेट से इतना लगाव है कि वह अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत के इस स्टार बल्लेबाज ने स्पष्ट किया कि अगर किसी विशेष 'माहौल' में उनकी योग्यता पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, तो उन्हें यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि वह 'जगह' उनके लिए नहीं बनी है। इस 37 वर्षीय सुपरस्टार ने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉडकास्ट पर कहा कि उन्हें अपने महत्व को लेकर किए जा रहे आकलन में लगातार बदलाव से नफरत है। कोहली ने कहा, ''मैं हमेशा तैयार रहता हूं क्योंकि यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है। मैं कसरत करता हूं, हम घर पर अच्छा खाना खाते हैं। मुझे इस तरह जीना पसंद है। यह केवल क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि 2027 के विश्व कप को लेकर होने वाली बातें और बाकी सब। मुझे कई बार पूछा गया है कि क्या आप 2027 में खेलना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा, ''मुझे इसका जवाब पता है और अगर मैं खेल रहा हूं तो फिर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं खेलना जारी रखना चाहता हूं। भारत के लिए विश्व कप खेलना शानदार है।'' कोहली ने कहा, ''मेरा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। मैं जिस माहौल का हिस्सा हूं उसमें कुछ योगदान दे सकता हूं और टीम को भी लगता है कि मैं योगदान दे सकता हूं, तो मैं खेलता रहूंगा। अगर मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करने की जरूरत महसूस कराई जाती है तो मैं उस माहौल में नहीं रह सकता।'' कोहली 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय और 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब केवल वनडे में खेलते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बहुत कम वनडे मैच खेले जा रहे हैं जिससे कोहली कम अवसरों पर ही भारत का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कोहली और एक अन्य स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के टीम का हिस्सा बनने की उनकी इच्छा के बावजूद उनके भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। कोहली ने कहा कि जब तक टीम को उनकी जरूरत होगी, वह टीम के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं अपनी तैयारियों के प्रति ईमानदार हूं, मैं खेल के प्रति अपने दृष्टिकोण के प्रति ईमानदार हूं। मैं पूरी लगन से मेहनत करता हूं। जब मैं खेलने के लिए जाता हूं तो मैं दूसरों से कम नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा मेहनत करता हूं और सही तरीके से खेलता हूं।'' कोहली ने खेल के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में कहा कि वह हमेशा कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं इसी तरह से तैयारी करता हूं। मैं 50 ओवर तक फील्डिंग करने के लिए तैयार हूं। इस तरह से खेलने के बाद भी अगर मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करनी पड़े, तो वह जगह मेरे लिए नहीं है।''

शास्त्री ने भविष्य में भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तानी के लिए सैमसन का समर्थन किया

दुबई : पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का कहना है कि भारत को टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन अगले दो-तीन साल में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी के लिए एक मजबूत दावेदार होंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुआई में भारतीय टीम ने दो महीने पहले घरेलू मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब जीता था जिसमें 31 वर्षीय सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था। शास्त्री ने कहा कि जब 2028 में अगला टी20 विश्व कप आएगा तब तक भारत को शायद सूर्यकुमार की जगह लेने के लिए किसी को ढूंढना पड़ सकता है क्योंकि उस समय मौजूदा कप्तान 37 साल के हो चुके होंगे।

सिंधू और लक्ष्य थाईलैंड ओपन से बाहर, सात्विक-चिराग की जोड़ी आगे बढ़ी

बैंकॉक : भारत की स्टार शटलर पी वी सिंधू और लक्ष्य सेन का थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सफर शुक्रवार को क्वार्टरफाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया, जबकि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई। बैंकॉक में खेले गए महिला एकल क्वार्टरफाइनल में सिंधू ने जापान की शीर्ष वरीय अकाने यामागुची के खिलाफ पहला गेम जीतकर शानदार शुरुआत की, लेकिन बाद में लय कायम नहीं रख सकीं और 21-19, 18-21, 15-21 से हार गईं। दूसरे गेम में सिंधू 5-1 से आगे थीं, लेकिन लगातार गलतियों का फायदा उठाकर यामागुची ने वापसी की और मैच अपने नाम कर लिया।

केकेआर उम्मीद जीवंत बनाए रखने उतरेगा, गुजरात टाइटंस की निगाह शीर्ष दो में जगह बनाने पर

कोलकाता : गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स शनिवार को ईडन गार्डन्स में होने वाले अहम मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत दर्ज कर अपनी प्लेऑफ उम्मीदें जीवंत रखने उतरेगी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है, क्योंकि एक और हार टीम को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर सकती है।केकेआर अब तक निरंतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। टीम को शुरुआती छह मैचों में सिर्फ एक जीत मिली थी, हालांकि बाद में उसने लगातार चार मुकाबले जीतकर वापसी की। पिछले मैच में विराट कोहली के शतक की बदौलत उसे आरसीबी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की संभावित वापसी टीम के लिए राहत की खबर है। बल्लेबाजी में युवा अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह ने प्रभावित किया है।दूसरी ओर शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस शानदार फॉर्म में है और शीर्ष दो में जगह मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। टीम के पास 16 अंक हैं और गेंदबाजी में राशिद खान, मोहम्मद सिराज और कैगिसो रबाडा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्लेबाजी में साई सुदर्शन लगातार रन बनाकर टीम की ताकत बने हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए किशन को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जीतने में अपने शानदार प्रदर्शन से योगदान देने के लिए इशान किशन को शुक्रवार को एक करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया। राज्य के नवादा जिले से संबंध रखने वाले और बचपन का शुरुआती समय पटना में बिताने वाले किशन ने मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर उनसे मुलाकात की। चौधरी ने इस 27 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने किशन के गले में अंगवस्त्र डाला, स्मृति-चिह्न भेंट किया और फिर एक करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर साझा पोस्ट में कहा, आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज और बिहार के बेटे इशान किशन जी को विश्व कप जीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और किशन के करीबी परिजन भी मौजूद रहे।

सुपर जायंट्स ने सात विकेट की जीत के साथ सुपर किंग्स के प्लेऑफ की उम्मीदों को दिया झटका

लखनऊ : लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुक्रवार को खेले गए आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को सात विकेट से हराकर उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका दिया। लखनऊ ने 188 रन का लक्ष्य 16.4 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार से चेन्नई का नेट रनरेट भी काफी गिर गया और टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर खिसक गई।लखनऊ की जीत के हीरो मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने 38 गेंदों में नौ चौके और सात छक्कों की मदद से 90 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने जोश इंग्लिश (35) के साथ पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़कर मैच को एकतरफा बना दिया। बाद में निकोल्स पूरन ने 17 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाकर टीम को शानदार जीत दिलाई। इससे पहले चेन्नई ने पांच विकेट पर 187 रन बनाए थे। युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने नाबाद 32 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में आकाश सिंह ने तीन विकेट लेकर चेन्नई को शुरुआती झटके दिए, लेकिन मार्श की तूफानी बल्लेबाजी के सामने सुपर किंग्स की चुनौती कमजोर पड़ गई।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर दस्तक देने की संभावना : आईएमडी

नयी दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल में दस्तक देने की संभावना है। आमतौर पर केरल में मानसून की शुरुआत एक जून के आसपास होती है, जिसके बाद यह उत्तर की ओर बढ़ते हुए देश के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। इसके साथ ही देश में मानसून मौसम (जून से सितंबर) की शुरुआत मानी जाती है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले वर्ष मानसून की शुरुआत 24 मई को हुई थी। आईएमडी ने कहा, ''इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल पहुंचने की संभावना है।'' उसने हालांकि कहा कि यह चार दिन पहले या चार दिन बाद भी पहुंच सकता है।

रक्षा सुरक्षा कोर के 'जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर' की गोलीबारी अभ्यास के दौरान मृत्यु

नागपुर: महाराष्ट्र के वर्धा जिले में शुक्रवार को केंद्रीय गोला-बारूद डिपो की पुलगांव फायरिंग रेंज में गोलीबारी अभ्यास के दौरान एक दुर्घटना में रक्षा सुरक्षा कोर के एक 'जूनियर कमीशन्ड अधिकारी' की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति में उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात उपक्षेत्र से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए यह खबर साझा की। विज्ञप्ति में कहा गया है, अफसोस के साथ सूचित किया जाता है कि 15 मई, 2026 को पुलगांव स्थित केंद्रीय गोला बारूद डिपो में नियमित गोलीबारी अभ्यास के दौरान, रक्षा सुरक्षा कोर के जेसीओ सूबेदार मेजर ओम बहादुर खंड, की फायरिंग रेंज में गोलीबारी के दौरान हुई एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले की जांच जारी है। रक्षा सुरक्षा कोर भारतीय सेना की विशेष कोर है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के प्रतिष्ठानों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब की अनुमति देने के फैसले का 'विहिप' ने विरोध किया

बेंगलुरु: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार के राज्य भर के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया और इस प्रतिबंध को हटाने वाले सरकारी आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की। विहिप ने यह मांग राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालयों में हिजाब, जनेऊ, शिवधारा और रुद्राक्ष पहनने की अनुमति देने वाला आदेश पारित करने के दो दिन बाद की है। राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें हिजाब बनाम भगवा शॉल विवाद के बाद सरकारी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। विहिप इसे 'तुष्टीकरण की राजनीति' मानती है। विहिप ने एक बयान में कहा कि पांच फरवरी 2022 के सरकारी आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133(2) के अंतर्गत जारी किए गए थे। बयान के अनुसार, यह आदेश संस्थानों को अनुशासन, एकरूपता और कक्षाओं को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए स्कूली पोशाक निर्धारित करने का अधिकार देता था। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि शैक्षणिक परिसरों को ऐसे धार्मिक प्रतीकों से मुक्त रहना चाहिए जो छात्रों के बीच अलगाव पैदा करते हैं।

यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर और अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई पुलिस ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर और अन्य के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपये की गिरवी रखी संपत्ति के कथित अवैध हस्तांतरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बैंक ने 150 करोड़ रुपये के ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए बिना एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि एचडीआईएल की अनुषंगी कंपनी सफायर लैंड डेवलपमेंट से जुड़े लखमिंदर दयाल सिंह की शिकायत पर वर्ली पुलिस थाने में कपूर, सुधीर वालिया और अन्य बैंक अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के मुताबिक, एचडीआईएल समूह की एक अन्य कंपनी, प्रिविलेज पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2015 में यस बैंक की वर्ली शाखा से 300 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

कुछ बेरोजगार युवा 'कॉकरोच' की तरह हैं, व्यवस्था पर हमला करते हैं : सीजेआई

वरिष्ठ अधिवक्ता के दर्जे को लेकर सुनवाई में सीजेआई की सख्त टिप्पणी

नयी दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना ''कॉकरोच'' से करते हुए शुक्रवार को कहा कि वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर व्यवस्था पर हमला शुरू कर देते हैं। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा हासिल करने के लिए 'प्रयासरत' रहने पर एक वकील को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे 'परजीवी' मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और पूछा कि क्या याचिकाकर्ता भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, 'पूरी दुनिया वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की पात्र हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके पात्र नहीं हैं।' सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि दिल्ली उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्रदान भी कर दे, तो शीर्ष अदालत उसके पेशेवर आचरण को देखते हुए उसे रद्द कर देगी। सीजेआई ने फेसबुक पर याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं?' न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न कोई रोजगार मिलता है और न ही किसी पेशे में उनका कोई स्थान होता है। उनमें से कुछ मीडिया के क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बनते हैं, कुछ सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बनते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।' पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उसके पास कोई अन्य मुकदमा नहीं है। पीठ ने सवाल किया, ''क्या यह उस व्यक्ति का आचरण है जो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने की इच्छा रखता है?' शीर्ष अदालत ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, और इसके लिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'आप इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या यह उचित लगता है?' अदालत ने यह भी पूछा कि क्या वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा एक तमगा है जिसे केवल सजावट के तौर पर रखना होता है। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उन कई लोगों की डिग्रियों की जांच कराने पर विचार कर रही है जो काला कोट पहनते हैं, क्योंकि उनकी डिग्रियों की प्रामाणिकता को लेकर गंभीर संदेह हैं। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर भारतीय विधिक परिषद कभी कुछ नहीं करेगी क्योंकि उन्हें 'अपने वोट चाहिए'। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पीठ से माफी मांगी और याचिका वापस लेने की अनुमति चाही। पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत 'बड़ी भूमिका' निभा सकता है: अराघची

नयी दिल्ली: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति के लिए 'बड़ी भूमिका' निभा सकता है। अराघची ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का कोई सैन्य समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति इस समय बेहद जटिल है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए नयी दिल्ली में मौजूद अराघची ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट का बातचीत के जरिए समाधान निकालने के अलावा कोई और हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, 'हम भारत की किसी भी रचनात्मक भूमिका का स्वागत करेंगे।' अमेरिका के साथ बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि यह ''विश्वास की कमी' के कारण प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, 'ईरान के पास अमेरिका पर भरोसा न करने के सभी कारण हैं, जबकि अमेरिकियों के पास हमपर (ईरान पर) भरोसा करने के सभी कारण हैं।' अराघची ने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता अभी तक विफल नहीं हुई है।

पश्चिम एशिया संघर्ष पर मतभेद को लेकर संयुक्त बयान के बिना समाप्त हुआ ब्रिक्स सम्मेलन

पश्चिम एशिया संघर्ष पर मतभेद के मद्देनजर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री शुक्रवार को दो दिवसीय सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त बयान जारी करने में विफल रहे। इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति न बन पाने के लिए यूएई को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में गतिरोध जारी रहने पर, मेजबान के रूप में नयी दिल्ली ने अध्यक्ष का वक्तव्य और इसके परिणाम से जुड़ा दस्तावेज जारी किया, जिसमें दो विशिष्ट अनुच्छेद शामिल थे जिन पर सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। इन अनुच्छेदों में फलस्तीनी प्राधिकरण के तहत वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को एकजुट करने के महत्व का उल्लेख था और साथ ही लाल सागर और बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य में सभी देशों के जहाजों के लिए नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग की गई थी।

सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के मूल्यांकन में पारदर्शिता का आश्वासन दिया

नयी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच अपनी 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएमएस) प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि यह व्यवस्था मूल्यांकन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। सीबीएसई ने कहा कि छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन का विकल्प जारी रहेगा। 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) 2026 से सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई एक डिजिटल प्रक्रिया है। इसमें उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है।

कर्नाटक: ट्रैक्टर के पुल से गिरने से छह लोगों की मौत, नौ घायल

कोप्पल (कर्नाटक): कोप्पल जिले में शुक्रवार को एक ट्रक से टकराने के बाद एक ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया जिससे छह लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि टक्कर के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। यह दुर्घटना मुनिराबाद पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले तुंगभद्रा पुल पर हुई। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के समय ट्रैक्टर की ट्रॉली में 15 यात्री सवार थे जो हुलिगे मंदिर जा रहे थे। प्रारंभिक जांच के आधार पर कोप्पल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरसिद्दी ने बताया कि ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिससे वह पुल से नीचे गिर गया। पुलिस ने कहा कि छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीकर में नीट की परीक्षा देने वाले एक छात्र ने आत्महत्या की: पुलिस

जयपुर: राजस्थान के सीकर में एक छात्र ने शुक्रवार को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने कहा कि छात्र राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक (यूजी) की तैयारी कर रहा था और उसने हाल में यह परीक्षा दी थी। उद्योग नगर के थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान प्रदीप मेघवाल के रूप में हुई है जो झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी इलाके में कनिका की ढाणी गांव का रहने वाला था। थानाधिकारी ने कहा कि वह अपनी दो बहनों के साथ सीकर के जलधारी नगर में किराए के मकान में रह रहा था और नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार प्रदीप ने कथित तौर पर अपनी बहन की चुन्नी से फांसी लगा ली। उस समय उसकी एक बहन कोचिंग क्लास में थी और दूसरी बाथरूम में थी। अधिकारियों ने बताया कि उसकी बड़ी बहन ने उसे फंदे से लटका हुआ देखा एवं उसे नीचे उतारने के बाद मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी ने बताया कि शव को मुर्दाघर में रखवाया गया है और अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। छात्र के पिता राजेश कुमार मेघवाल ने पुलिस को बताया कि प्रदीप की नीट की परीक्षा अच्छी हुई थी और परिवार को उम्मीद थी कि उसे करीब 650 अंक मिलेंगे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि छात्र की परीक्षा अच्छी गई थी। उसके पिता के बयान का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र को 650 अंकों की उम्मीद थी। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने इसे नीट परीक्षा 2026 में अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरों के बाद छात्रों में बढ़ रही चिंता से जोड़ा है।

सैटेलाइट टैग लगा देश का पहला गंगा सॉफ्टशेल कछुआ काजीरंगा में छोड़ा गया

गुवाहाटी: असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देश का पहला सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्टशेल कछुआ शुक्रवार को छोड़ा गया। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह पहल 'लुप्तप्राय प्रजाति दिवस' के अवसर पर की गई। उन्होंने कहा, ''काजीरंगा में भारत के लिए एक नयी शुरुआत। 'एंडेंजर्ड स्पीशीज डे' के अवसर पर सैटेलाइट टैग लगा देश का पहला गंगा सॉफ्टशेल कछुआ काजीरंगा में छोड़ा गया, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।' मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह असम के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हम अपने जंगलों में रहने वाली हर प्रजाति की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं।'' गंगा सॉफ्टशेल कछुआ मीठे पानी में रहने वाला एक सरीसृप है, जो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी भारत की गंगा, सिंधु और महानदी नदी प्रणालियों तक सीमित है। कछुए की यह प्रजाति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के भाग-2 में सूचीबद्ध है और कानून के तहत इस कछुए को अपने पास रखना अपराध है।

बस में सामूहिक बलात्कार मामला: पैसों को लेकर विवाद का पहलू सामने आया

नयी दिल्ली: बाहरी दिल्ली में एक निजी स्लीपर बस के अंदर 30 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की जांच कर रही पुलिस के सामने पीड़िता और आरोपियों के बीच पैसों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यहां मंगोलपुरी इलाके में 11 मई को महिला को कथित तौर पर बस के अंदर खींचने के बाद चालक व परिचालक ने उसके साथ बलात्कार किया। दोनों आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों के साथ पैसों को लेकर विवाद हुआ था। सूत्रों ने यह भी बताया कि आरोपियों में से एक घटना के बाद मौके से फरार नहीं हुआ और बाद में पीड़िता ने उसके मोबाइल फोन से पुलिस को फोन किया।

लुधियाना में 'अब तक के सबसे बड़े' अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, 132 गिरफ्तार

लुधियाना: लुधियाना पुलिस ने शुक्रवार को शहर में अब तक के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जिसमें फर्जी कॉल सेंटर चलाने में कथित तौर पर शामिल 132 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह पॉप-अप स्कैम, दूर बैठे कंप्यूटर तक पहुंच हासिल कर धोखाधड़ी और फर्जी बैंक सुरक्षा अलर्ट के माध्यम से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाता था। पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस गिरोह के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर हाल ही में संधू टॉवर और सिल्वर ओक के पास स्थित व्यावसायिक परिसरों सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान विभिन्न

अवैध कॉल सेंटर से कुल 132 लोगों को पकड़ा गया। यह गिरोह परिष्कृत ऑनलाइन धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों के माध्यम से विदेशी नागरिकों को निशाना बना रहा था। उन्होंने बताया कि 1.07 करोड़ रुपये, 98 लैपटॉप, 229 मोबाइल फोन और 19 वाहन बरामद किए गए हैं। 300 से अधिक बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाई गयी है और कई अन्य खातों के लिये यह प्रक्रिया जारी है। आयकर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और वे जांच में शामिल हो गए हैं। लुधियाना के साइबर अपराध पुलिस थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

न्यायालय ने विमान किरायों को तर्कसंगत बनाने और केंद्र से लोगों को राहत देने को कहा

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि विमान किरायों को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए और उसने केंद्र सरकार से यात्रियों को राहत प्रदान करने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस बात को रेखांकित किया कि एक ही दिन, एक ही हवाई मार्ग पर उड़ान भरने वाली एक एयरलाइन एक निश्चित किराया वसूलती है जबकि दूसरी एयरलाइन अलग किराया वसूलती है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने कहा, ''इस विसंगति के कारण लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश करें। एक ही दिन, एक ही मार्ग पर चलने वाली उड़ानों के लिए, एक एयरलाइन 'इकोनॉमी' श्रेणी के लिए 8000 रुपये लेती है जबकि दूसरी एयरलाइन 18000 रुपये किराया लेती है।' न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, 'विमान किरायों को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।'' इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2024 का एक नया अधिनियम लागू हो गया है और संबंधित नियमों पर परामर्श की प्रक्रिया जारी है। मेहता ने कहा कि सरकार इस समस्या पर विवाद नहीं कर रही है और इस मुद्दे को गैर-विवादास्पद मानते हुए इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। पीठ सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में देश में निजी एयरलाइनों के विमान किरायों और अन्य शुल्कों में 'अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव' को सुव्यवस्थित करने संबंधी नियामक दिशानिर्देशों का अनुरोध किया गया था। लक्ष्मीनारायणन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विमान अधिनियम 1937 के तहत नियम पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनका पालन नहीं किया गया। मेहता ने इस बात पर सहमति जताई कि पुराने नियम अभी भी लागू हैं, लेकिन भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत नए नियम बनाए जा रहे हैं, जो जनवरी 2025 में लागू हुआ था। श्रीवास्तव ने कहा कि जब तक नये नियम नहीं बन जाते, पुराने नियम लागू रहेंगे और इसमें कहा गया है कि यदि डीजीसीए इस बात से संतुष्ट है कि किसी विशेष स्थिति में, एयरलाइन अनुचित या अत्यधिक किराया वसूल रही हैं, तो वह निर्देश जारी करेगा। उन्होंने कहा, 'वे कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं। नियम मौजूद हैं, शक्तियां भी मौजूद हैं, लेकिन यह शक्तियों के प्रयोग न करने का मामला है।' पीठ ने श्रीवास्तव से केंद्र द्वारा दायर हलफनामे का जवाब देने को कहा और सॉलिसिटर जनरल के इस कथन को दर्ज किया कि नयी व्यवस्था के तहत नियम बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया जारी है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 13 जुलाई तय की। उच्चतम न्यायालय ने देश में निजी एयरलाइनों के विमान किरायों और अन्य शुल्कों में 'अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव' को सुव्यवस्थित करने संबंधी नियामक दिशानिर्देशों का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर हलफनामा दाखिल नहीं करने को लेकर 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी।

मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर समान कानूनों और प्रक्रियाओं की जरूरत : अमित शाह

नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रेखांकित किया कि मादक पदार्थों की तस्करी, और इसके सरगनाओं के प्रत्यर्पण और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए वैश्विक स्तर पर समान कानून और प्रक्रिया की आवश्यकता है। शाह ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) द्वारा आयोजित आर एन काव स्मारक व्याख्यान-2026 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2047 तक नशामुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह व्याख्यान रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ काव की स्मृति में आयोजित किया जाता है। शाह ने 'मादक पदार्थ: एक सर्वव्यापी खतरा, एक सामूहिक जिम्मेदारी' विषय पर अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मादक पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए एक खाका तैयार किया है। रॉ के मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और राजनयिकों ने हिस्सा लिया। शाह ने कहा कि सभी जिम्मेदार देशों के पास अब भी मादक पदार्थों के खतरे को हराने के लिए मिलकर काम करने का समय है। उन्होंने आगाह किया कि यदि अब संयुक्त प्रयास शुरू नहीं किए गए, तो दस साल बाद

दुनिया को एहसास होगा कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इसके द्वारा किए गए नुकसान को ठीक करना संभव नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'दुनिया को एक साथ मादक पदार्थों के नेटवर्क और मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवादी राष्ट्रों, दोनों से लड़ना होगा। इस लड़ाई में, दुनिया को प्रतिबंधित पदार्थों की एक समान परिभाषा, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मानकीकृत दंड, मादक पदार्थों के सरगनाओं के प्रत्यर्पण और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एकसमान कानून अपनाने होंगे।' उन्होंने कहा कि जब तक विनियमित पदार्थों के रूप में नामित किए जाने वाले पदार्थों पर वैश्विक स्तर पर उच्च स्तर का सामंजस्य नहीं होता है, साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के लिए समान मानक दंड निर्धारित नहीं होते हैं, तब तक गिरोह नीति में विसंगतियों का फायदा उठाते रहेंगे, जिससे लड़ाई कमजोर होती जाएगी। शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मादक पदार्थों की खेप को रोकने और मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के सरगनाओं को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने के लिए वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर आम सहमति की आवश्यकता को रेखांकित किया कि मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और 'नार्को-देशों'' को वैकल्पिक शक्ति केंद्र बनने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। शाह ने उपस्थित राजदूतों और राजनयिकों से मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध में भारत के प्रयासों में शामिल होने की अपील की। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के प्रति भारत की ' कतई बर्दाश्त नहीं' नीति के तहत, देश यह सुनिश्चित करेगा कि एक ग्राम मादक पदार्थ देश में प्रवेश न कर सके या भारत को पारगमन मार्ग के रूप में उपयोग करके देश से बाहर न जा सके।

बदरीनाथ-केदारनाथ में दिव्यांगों, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन

देहरादून : उत्तराखंड के बदरीनाथ व केदारनाथ मंदिरों में आने वाले 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कर सकेंगे। श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने इस संबंध में आदेश जारी किये। द्विवेदी ने बताया कि मंदिर समिति द्वारा बदरीनाथ एवं केदारनाथ धाम में दिव्यांग और वृद्ध भक्तों को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी हैं। मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी रांगड़ ने बताया कि निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए प्राथमिक दर्शन व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके तहत दोनों धामों में दिन भर में 15-15 मिनट के चार स्लॉट में उन्हें दर्शन कराए जाएंगे। एक धाम में 15 मिनट के एक स्लॉट में 50 वृद्ध व दिव्यांग श्रद्धालु दर्शन करेंगे और इस प्रकार प्रत्येक धाम में हर दिन एक घंटे की अवधि में ऐसे 200 भक्तों को प्राथमिक दर्शन की सुविधा मिलेगी।

उन्नाव बलात्कार मामला: न्यायालय ने सेंगर की सजा निलंबित करने का आदेश

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही उच्च न्यायालय से याचिका पर नए सिरे से फैसला करने को कहा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय से यह भी कहा कि वह सेंगर की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ दायर मुख्य याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास करे। इसमें कहा गया कि यदि उच्च न्यायालय के लिए मुख्य याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेना संभव नहीं है तो उसे वहां ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से पहले सेंगर की उस याचिका पर आदेश पारित करना चाहिए जिसमें मामले में आजीवन कारावास को निलंबित करने की मांग की गई है।

भारत, ब्रिटेन इस्पात मुद्दे को सुलझाने के लिए कर रहे काम

नयी दिल्ली : वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिटेन के हाल के इस्पात संरक्षण उपाय से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए भारत और ब्रिटेन 'विशिष्ट एवं रचनात्मक समाधान' तलाश रहे हैं ताकि प्रस्तावित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) को जल्द लागू किया जा सके। दोनों देशों ने 24 जुलाई 2025 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सचिव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हम इसे लागू करने के बहुत करीब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अड़चनें हैं। ब्रिटेन हाल ही में एक इस्पात उपाय लेकर आया है जिसे भारत-ब्रिटेन समझौते की वार्ता के दौरान ध्यान में नहीं रखा गया था। हम इस इस्पात उपाय पर भी एक विशिष्ट, रचनात्मक समाधान खोजने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भारत-ब्रिटेन सीईटीए को जल्द लागू किया जा सके।'' ब्रिटेन एक जुलाई 2026 से शुल्क-मुक्त इस्पात आयात पर सीमा लागू करेगा जिससे कुल कोटा मात्रा इस्पात संरक्षण उपाय की तुलना में 60 प्रतिशत कम हो जाएगी। इन स्तरों से अधिक आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। यह उपाय उन इस्पात उत्पादों के आयात पर लागू होगा जिनका उत्पादन ब्रिटेन में भी किया जा सकता है।

सोने का आयात अप्रैल में 82 प्रतिशत बढ़ा, चांदी का आयात 157 प्रतिशत उछला

नयी दिल्ली : सोने की ऊंची कीमतों के बीच अप्रैल में भारत का सोने का आयात 81.69 प्रतिशत बढ़कर 5.62 अरब डॉलर हो गया। हालांकि, सरकार के आयात शुल्क बढ़ाने के बाद आने वाले महीनों में इसमें कमी आने की संभावना जताई गई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में चांदी का आयात 157.16 प्रतिशत बढ़कर 41.1 करोड़ डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात मूल्य के लिहाज से 24 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि, मात्रा के लिहाज से आयात 4.76 प्रतिशत घटकर 721.03 टन रहा। सरकार ने 13 मई से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि आयात शुल्क बढ़ने से वर्ष के दौरान सोने और चांदी के आयात पर असर पड़ेगा और इनमें कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि चांदी का औद्योगिक उपयोग अधिक होने के कारण उस पर शुल्क वृद्धि का असर अपेक्षाकृत कम हो सकता है। अग्रवाल ने कहा कि शुल्क बढ़ने के बाद उपभोग आधारित मांग में कमी आने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सोने के आयात के बारे में उन्होंने कहा कि 2025-26 में मूल्य और मात्रा दोनों के लिहाज से आयात घटा है, जिससे भारत के कुल स्वर्ण आयात में यूएई की हिस्सेदारी कम हुई है। भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत रियायती शुल्क पर सोने के आयात के लिए शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) व्यवस्था लागू की गई थी। यह समझौता एक मई, 2022 से प्रभावी हुआ। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में कुल स्वर्ण आयात 795 टन और 2024-25 में 757 टन रहा। इनमें टीआरक्यू व्यवस्था के तहत आयात की हिस्सेदारी क्रमशः लगभग पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2025-26 में इस व्यवस्था के तहत 8.58 टन सोना आयात की अनुमति दी गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 721 टन सोना आयात किया।

वैश्विक बिकवाली से चांदी 21,600 रुपये टूटी, सोना 3,200 रुपये लुढ़का

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी का भाव 21,600 रुपये टूटकर 2.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गया जबकि सोने की कीमत 3,200 रुपये टूटकर 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मजबूत डॉलर और निवेशकों की भारी मुनाफावसूली से यह गिरावट आई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने कहा कि 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 3,200 रुपये यानी 1.93 प्रतिशत टूटकर 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर मिलाकर) रह गया। बृहस्पतिवार को बाजार बंद होने के समय इसकी कीमत 1,66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। चांदी की कीमतें भी 21,600 रुपये यानी 7.3 प्रतिशत टूटकर 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर समेत) रह गईं। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत 2,96,600 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

गौतम अदाणी छह लाख डॉलर, सागर अदाणी 1.2 करोड़ डॉलर का भरेंगे जुर्माना

मुकदमे का निपटारा करेगा अमेरिका

न्यूयॉर्क : अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के जुर्माना देने पर राजी होने के बाद उनसे जुड़े मुकदमे का निपटारा करने पर सहमति जताई है। अदालत के बृहस्पतिवार को जारी दस्तावेजों से यह जानकारी मिली। मामले के अनुसार अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गौतम अदाणी और अन्य ने भारतीय अधिकारियों को सौर ऊर्जा अनुबंध पाने के लिए रिश्वत देने की साजिश रची और अमेरिकी निवेशकों से इसे छिपाया। वर्ष 2024 के अंत में दायर इस मुकदमे में अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने गौतम अदाणी और ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रमुख तथा उनके भतीजे सागर अदाणी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को करोड़ों डॉलर के बराबर राशि देने का वादा किया और उसके एवज में ऊर्जा खरीद अनुबंध हासिल किए। साथ ही, कंपनी ने अमेरिका के निवेशकों से कई अरब डॉलर जुटाए जिन्हें कथित रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि कंपनी के पास मजबूत भ्रष्टाचार-रोधी अनुपालन कार्यक्रम है और वरिष्ठ प्रबंधन की ओर से यह वादा किया गया था कि कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी। एसईसी ने उस समय कहा था कि ये कार्रवाइयां अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। अमेरिकी अदालत की ओर से जारी दस्तावेजों के अनुसार, गौतम अदाणी ने छह लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना जबकि उनके भतीजे सागर अदाणी ने 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमति जतायी है। प्रस्तावित समझौते में किसी भी प्रकार के अपराध की स्वीकारोक्ति शामिल नहीं है। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने उस समय आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया था। बृहस्पतिवार को गौतम तथा सागर के वकीलों को भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला।

चीन को भारत का निर्यात अप्रैल में 27 प्रतिशत बढ़ा, आयात में 20.85 प्रतिशत की वृद्धि

नयी दिल्ली : भारत का चीन को निर्यात अप्रैल में 27 प्रतिशत बढ़ा, जबकि उसी अवधि में चीन से आयात 20.85 प्रतिशत बढ़ गया। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। अप्रैल 2026 में चीन को निर्यात बढ़कर 1.77 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1.39 अरब डॉलर था। इसी तरह चीन से आयात बढ़कर 11.97 अरब डॉलर पहुंच गया, जो अप्रैल 2025 में 9.90 अरब डॉलर था। इस दौरान भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 10.2 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 8.51 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार चीन ने वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इस अवधि में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 112.16 अरब डॉलर रहा। अमेरिका 2024-25 तक लगातार चार वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था।

रॉश ने भारत में फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए इंजेक्शन पेश किया

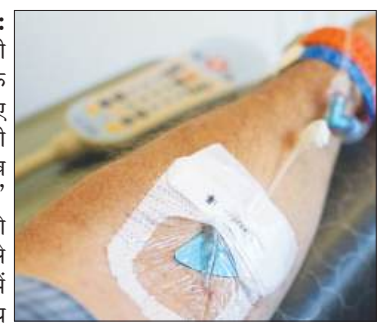

नयी दिल्ली : स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रॉश ने भारत में फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए त्वचा के नीचे दी जाने वाली अपनी एटजोलिजुमैब इंजेक्शन 'टिसेंट्रिक एससी' को पेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि इससे मरीजों का अस्पतालों में बिताया जाने वाला समय कम होगा। रॉश फार्मा इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि फेफड़ों के कैंसर के लिए यह सबक्यूटेनियस (त्वचा के नीचे दी जाने वाली) इम्यूनोथेरेपी करीब सात मिनट में दी जा सकती है, जबकि पारंपरिक आईवी (इंट्रावीनस) इन्फ्यूजन में कई घंटे लग सकते हैं। रॉश फार्मा इंडिया के चिकित्सा एवं नियामक मामलों के निदेशक डॉ. सिवाबालन सिवानेसन ने बताया ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, दवा देने में लगने वाला समय लगभग 80 प्रतिशत तक कम हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की पूर्व तैयारी और दवा चढ़ाने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने कहा, इस दवा को देने की प्रक्रिया चार से आठ मिनट के बीच पूरी हो जाती है और औसतन लगभग सात मिनट लगते हैं। इसलिए कुल मिलाकर इलाज देने का समय काफी कम हो जाता है। सिवानेसन बताया कि भारत में हर वर्ष लगभग 80,000 फेफड़ों के कैंसर के मरीजों का पता चलता है, जिनमें अधिकतर मामले गंभीर अवस्था में होते हैं। उन्होंने कहा, इस अनूठी दवा से यह तय होगा कि हम कितने अधिक मरीजों तक पहुंच बना सकते हैं।

कमजोर रुपये, मुद्रास्फीति की चिंता से बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 161 अंक फिसला

मुंबई : घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट के साथ बंद हुए। धातु, तेल एवं गैस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयरों में बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच निवेशकों में सतर्कता देखी गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स उतार-चढ़ाव के बीच 160.73 अंक यानी 0.21 प्रतिशत गिरकर 75,237.99 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने एक समय करीब 470 अंक तक की बढ़त ले ली थी। लेकिन बाद में बिकवाली के दबाव में यह नीचे आ गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी 46.10 अंक यानी 0.19 प्रतिशत गिरकर 23,643.50 पर बंद हुआ। इसके साथ ही दो दिनों से जारी तेजी पर लगाम लग गई। साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में कुल 2,090.2 अंक यानी 2.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि एनएसई निफ्टी 532.65 अंक यानी 2.2 प्रतिशत के नुकसान में रहा। शुक्रवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स की कंपनियों में से टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टुब्रो, ट्रेंट, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स के शेयरों में गिरावट रही। दूसरी तरफ, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, अदाणी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा में बढ़त दर्ज की गई। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, हाल में आई तेजी के बाद निवेशक सतर्क हो गए हैं। बढ़ते बॉन्ड प्रतिफल, कमजोर रुपये और ईंधन कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। नायर ने कहा कि चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों और आकर्षक मूल्यांकन से कुछ सहारा मिल रहा है, लेकिन निकट भविष्य में बाजार की दिशा वैश्विक घटनाक्रमों और भू-राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करेगी। इस बीच, रुपया पहली बार 96 के स्तर के नीचे फिसल गया और 95.94 प्रति डॉलर (अस्थायी) के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है जबकि सीएनजी कीमतों में दो रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.78 प्रतिशत गिर गया जबकि छोटी कंपनियों के स्मालकैप सेलेक्ट सूचकांक में 0.06 प्रतिशत की गिरावट रही। क्षेत्रवार सूचकांकों में धातु खंड में सर्वाधिक 1.98 प्रतिशत की नरमी रही जबकि रियल्टी खंड में 1.82 प्रतिशत, पीएसयू बैंक खंड में 1.80 प्रतिशत और तेल एवं गैस खंड में 1.79 प्रतिशत की गिरावट रही। बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 1,471 कंपनियां गिरावट के साथ बंद हुईं जबकि 1,705 कंपनियों में तेजी रही और 169 अन्य अपरिवर्तित रहीं।

भारत का व्यापार पश्चिम एशिया के साथ लगातार दूसरे महीने घटा

नयी दिल्ली : भारत का पश्चिम एशिया से व्यापार अप्रैल में लगातार दूसरे महीने घटा है। अमेरिका-इजराइल का ईरान के साथ युद्ध से पश्चिम एशिया क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्ग बाधित होने के कारण व्यापार में कमी आई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस अवधि में भारत का पश्चिम एशिया को होने वाला वस्तु निर्यात 28 प्रतिशत घटकर 4.16 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 5.78 अरब डॉलर था। इस क्षेत्र से आयात भी 31.64 प्रतिशत घटकर 10.47 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 15.32 अरब डॉलर था। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को भारत का निर्यात 36.39 प्रतिशत घटकर 2.18 अरब डॉलर और सऊदी अरब को 2.89 प्रतिशत घटकर 85.2 करोड़ डॉलर रहा। हालांकि, यूएई से आयात 34.63 प्रतिशत घटकर 4.07 अरब डॉलर रहा, जबकि सऊदी अरब से आयात 30.29 प्रतिशत बढ़कर 3.84 अरब डॉलर और ओमान से 246.42 प्रतिशत बढ़कर 1.48 अरब डॉलर रहा। मार्च में भी पश्चिम एशिया क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार 50 प्रतिशत से अधिक घटा था। अधिकारियों के अनुसार अमेरिका-इजराइल द्वारा फरवरी में ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर प्रतिबंध और बाधाएं बढ़ गई हैं। यह 33 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें यूएई, ओमान, ईरान, बहरीन और सऊदी अरब शामिल हैं। आमतौर पर भारत इस क्षेत्र को हर महीने लगभग छह अरब डॉलर का निर्यात करता है। इस गिरावट का असर रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद और चावल जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर पड़ा है।

आयकर के आईटीआर-1 एवं आईटीआर-4 फॉर्म दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुक्रवार को शुरू कर दी। ये फॉर्म मुख्य रूप से छोटे और मध्यम करदाताओं द्वारा भरे जाते हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। इन दोनों फॉर्म को 30 मार्च को अधिसूचित किया गया था। ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू होने के साथ ही करदाता अब आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जबकि आईटीआर-4 (गैर-ऑडिट मामलों) के लिए यह समयसीमा 31 अगस्त तय की गई है। आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म उन निवासी व्यक्तियों के लिए है, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय वेतन, एक मकान, ब्याज जैसे अन्य स्रोतों और 5,000 रुपये तक की कृषि आय से होती है। इसमें 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की सूचना भी दी जा सकती है।

अमेरिकी दल व्यापार वार्ता के लिए अगले महीने आ सकता भारत : वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली : वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी दल के अगले महीने भारत आने की संभावना है। हालांकि अभी उनके आने की तारीख तय नहीं हुई है। भारतीय दल अप्रैल में वॉशिंगटन गया था जहां अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक कर अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने एवं व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत वार्ताओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। सचिव ने संवाददाताओं से कहा, '' हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी दल जल्द आएगा। इस महीने नहीं, शायद अगले महीने आएगा...।'' उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और इस पर उपयुक्त समय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही भारत धारा-301 के तहत जांच को लेकर भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है। भारत और अमेरिका ने सात फरवरी को संयुक्त बयान जारी कर द्विपक्षीय रूप से लाभकारी व्यापार के लिए अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी।

रुपये में गिरावट जारी रही तो ईंधन मूल्य वृद्धि का लाभ खत्म हो जाएगा: एसबीआई रिपोर्ट

नयी दिल्ली : रुपये में यदि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और भी गिरावट होती है तो तेल विपणन कंपनियों को वाहन ईंधन कीमतों में की गई बढ़ोतरी से मिलने वाला पूरा लाभ खत्म हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने यह कहा। 'एसबीआई इकोरैप' रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन कीमतों में यह बढ़ोतरी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को खुदरा बिक्री पर लागत के मुकाबले हो रहे नुकसान (अंडर-रिकवरी) में करीब 52,700 करोड़ रुपये की राहत दे सकती है, जो वित्त वर्ष 2026-27 में अपेक्षित कुल नुकसान का लगभग 15 प्रतिशत है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई तीव्र वृद्धि के बाद उठाया गया है। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि रुपये में अगर आगे भी गिरावट का रुख बना रहता है तो कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ जाएगी, जिससे कीमत वृद्धि का पूरा लाभ समाप्त हो सकता है। एसबीआई इकोरैप के मुताबिक, यदि रुपये में मौजूदा औसत स्तर से केवल दो रुपये की और कमजोरी आती है, तो आयात लागत इतनी बढ़ जाएगी कि ईंधन मूल्य वृद्धि का लाभ पूरी तरह चला जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रुपया पहले ही एक महत्वपूर्ण गिरावट स्तर के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद और कमजोरी घरेलू ईंधन कीमत संशोधन के लाभ को काफी हद तक खत्म कर सकती है।

वायदा बाजार में कच्चे तेल का भाव 117 रुपये बढ़कर 9,841 रुपये प्रति बैरल

नयी दिल्ली : मजबूत हाजिर मांग के बीच कारोबारियों के अपने सौदे बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार को 117 रुपये चढ़कर 9,841 रुपये प्रति बैरल हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर जून में आपूर्ति वाले कच्चे तेल के अनुबंधों की कीमत 117 रुपये या 1.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9,841 रुपये प्रति बैरल हो गई। इसमें 2,276 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि प्रतिभागियों के दांव बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहीं। वैश्विक स्तर पर, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कच्चे तेल की कीमत 1.30 प्रतिशत बढ़कर 102.49 डॉलर प्रति बैरल हो गई जबकि ब्रेंट कच्चा तेल न्यूयॉर्क में 1.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 106.98 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

केंद्र किसानों से 1,235 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदेगा: चौहान

पुणे/नासिक : केंद्र सरकार किसानों से 12.35 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 1,235 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्याज की कीमतों में जारी गिरावट के बीच यह घोषणा की है उन्होंने यह घोषणा महाराष्ट्र के सतारा में एक कार्यक्रम में की। महाराष्ट्र प्याज का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। चौहान ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण प्याज के निर्यात पर असर पड़ा है। यह संकट 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों के कारण शुरू हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने प्याज की कीमतों में आए संकट के बारे में फडणवीस से चर्चा की है। उन्होंने कहा, ''चूंकि पश्चिम एशिया संकट के कारण प्याज का निर्यात प्रभावित हुआ है, इसलिए प्याज की कीमतें गिर गई हैं। मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि आज (शुक्रवार) से ताजे प्याज की खरीद दर 12.35 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। हम किसानों का पूरा स्टॉक खरीदेंगे और प्याज उपजाने वालों को सहायता देंगे।'' उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाद में इसी कार्यक्रम में फडणवीस ने भी प्याज की खरीद दर को लेकर चौहान की घोषणा को दोहराया। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार की इस घोषणा से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों के चेहरों पर खुशी नहीं आई। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ (एमएसओजीए) ने कहा कि 1,235 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद दर पर्याप्त नहीं है। यह दर तो उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं करती और उन्होंने 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की समर्थन मूल्य की मांग की। उन्होंने उन किसानों के लिए मुआवजे की भी मांग की, जिन्होंने हाल के महीनों में बहुत कम कीमतों पर अपना प्याज बेचा है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

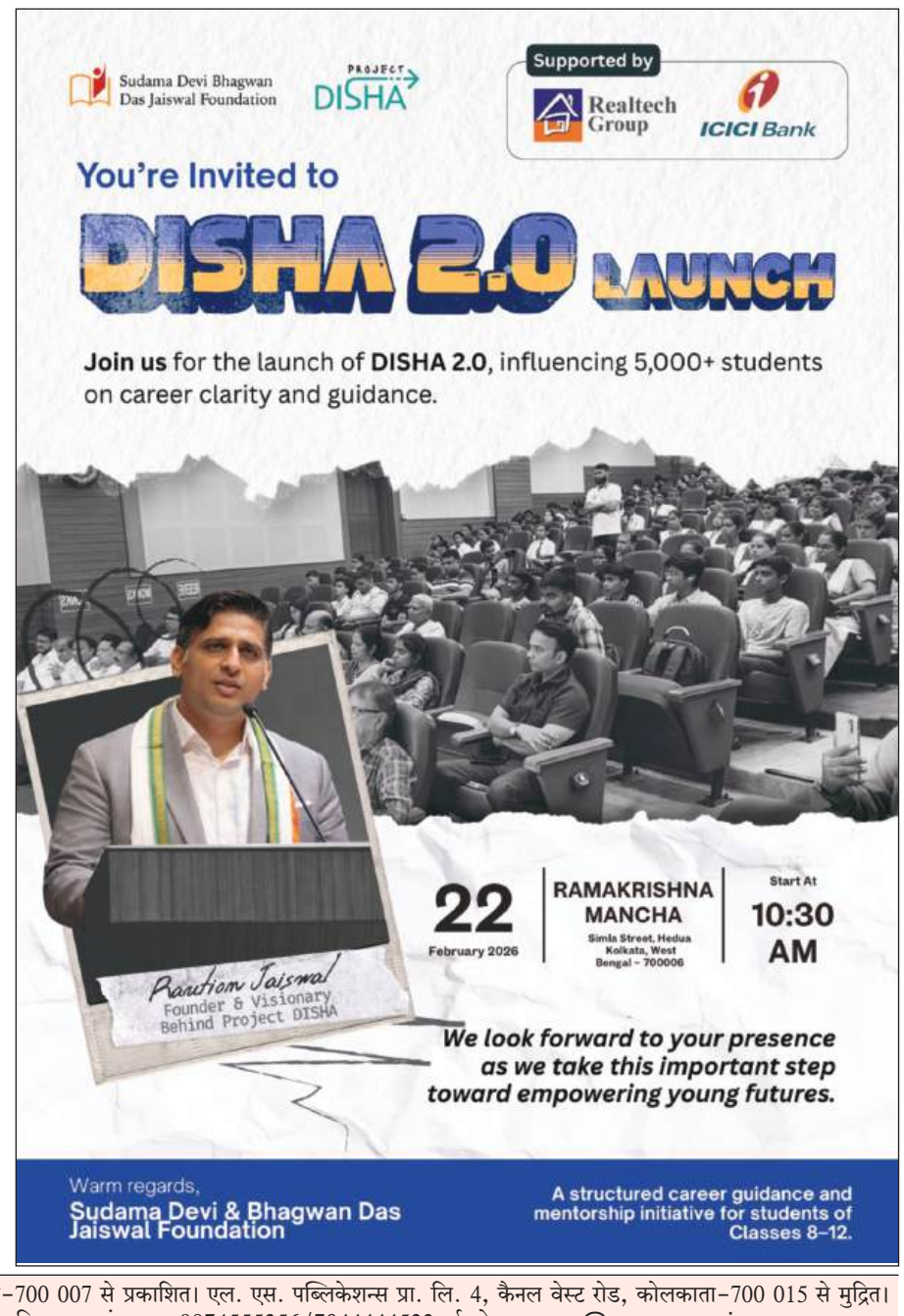

वर्ष 11, पूर्णांक 3593 अंक 059 RNI No WBHIN/2016/66788, सर्वांग प्रकाशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **सरोज राय** द्वारा रजि. 17, बालमुकुन्द मक्कर रोड, 2सरा तल्ला, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित। एल. एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता-700 015 से मुद्रित।
सम्पादक- **अनिल कुमार राय** (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी), कॉर्पोरेट आफिस : 230, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700 006, विज्ञापन एवं प्रसार-9874555256/7044444522, ई-मेल news@samagya.in